A Daily News Magazine
भोपाल
मंगलवार, 28 जुलाई, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 326, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

मजाक और तंज के जरिए राजनीतिक विरोध का नया तरीका

अंबिका नैथानी

जब छात्रों ने पहली बार दिल्ली के जंतर-मंतर के पास सड़कों पर उतरना शुरू किया, तो इंस्टाग्राम या X स्क्रॉल करना लगभग नामुमकिन हो गया था बिना ऐसे वीडियो देखे जिन पर लिखा होता था, 'सबसे ज्यादा गैर-सीरियस पीढ़ी।' सालों बाद पहली बार सत्ता में बैठे लोगों पर मजाक वापस आया, न कि उन लोगों पर जो दबे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के बनाए मीम, पोस्टर और तख्तियां ऐसे लग रहे थे जैसे वे सीधे सत्ता व्यवस्था पर तंज कस रहे हों।

कई प्रदर्शनकारी महात्मा गांधी और बीआर आंबेडकर के रूप में तैयार होकर आए थे। इंस्टाग्राम पर कैप्शन लिखा था, 'Season 1 players respawned।' यहा´ Season 1 का मतलब आजादी का आंदोलन था। हमने हाल के समय के सबसे प्रभावशाली आंदोलन में कई स्पाइडर-मैन और कॉकरोच को भी प्रदर्शन में शामिल देखा। इन पोशाकों और तैयार की गई प्रस्तुतियों के पीछे हमने एक ऐसी पीढ़ी देखी जो असल समय में दुख और त्रासदी से निपटने के लिए हास्य का इस्तेमाल कर रही थी।

लोगों की प्रतिक्रियाएं मोटे तौर पर दो हिस्सों में बंटी हुई थीं। पहला हिस्सा कहता था कि यह कोई हंसी-मजाक का मामला नहीं है। हिंसा, भूख हड़ताल और छात्रों की मौत जैसी चीजें पूरी गंभीरता मांगती हैं। यही वह सोच है, जिसके आधार पर कुछ लोग इस आंदोलन को कमजोर बताने की कोशिश भी कर रहे थे।

दूसरा हिस्सा छात्रों की इसी बात के लिए तारीफ कर रहा था कि वे गंभीर और उदास बने रहने से इनकार कर रहे हैं। वे खुद भी इस मजाक में शामिल हो रहे थे और उनकी बेपरवाही को लोकतांत्रिक विरोध के प्रति अपनी तरह की प्रतिबद्धता के रूप में देख रहे थे। अगर आप काफी देर तक स्क्रॉल करते रहें, तो आंदोलन से जुड़ी खास चीजें अपने आप एक अलग तरह की श्रेणी जैसी लगने लगती हैं। लोग मजाक कर रहे थे कि प्रदर्शन के लिए निकलते समय उन्हें मार पड़ने की उम्मीद है, लेकिन उसी समय वे 'रेट माय आउटफिट' (मेरे आउटफिट को रेट करो) वाला वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे।

मोबाइल गेम Subway Surfers का बैकग्राउंड म्यूजिक जब पुलिस से भागते प्रदर्शनकारियों के वीडियो के साथ जोड़ा गया, तो पुलिस की पीछा करने वाली घटना तुरंत एक मीम बन गई। हिरासत में लिए जाते समय भी लोग वायरल ऑडियो पर लिप-सिंक वीडियो बना रहे थे। उनके चेहरे के भाव और शरीर की भाषा दोनों ही सच्चे लग रहे थे।

एक वायरल वीडियो में मजाकिया अंदाज में बताया गया कि 'प्रदर्शन में क्या-क्या लेकर जाना चाहिए।' उसमें तैरने वाले चश्मे को S-tier में रखा गया था। जानकारी इस तरह साझा की जा रही थी कि वह भारी और समझने में मुश्किल न लगे। एक पत्रकार ने तो दिल्ली पुलिस के लिए तद्दठु´ की भाषा समझाने वाला वीडियो भी बनाया।

इन मजाक के पीछे कुछ बड़े प्रतीक मौजूद थे। छात्रों ने उन्हीं प्रतीकों की भाषा अपनाई, जिन पर राज्य अपना अधिकार जताता है। उन्होंने संविधान को ऊपर उठाया और राष्ट्रीय ध्वज को ढाल की तरह अपने ऊपर रखा। भीड़ ने दिल्ली पुलिस को आगे बढ़ने से रोकने की रणनीति के रूप में राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। ताकि सत्ता में बैठे लोगों से जवाब मांगा जा सके।

अगर मीम्स के नीचे छिपी असली बात को देखें, तो एक ज्यादा गंभीर तस्वीर सामने आती है। फोन और इंटरनेट ने लोगों को अपनी कहानियां बताने की जो आसानी और ताकत दी है, उससे हमें पता चलता है कि प्रदर्शनकारी क्या दिखाना चाहते थे। ऐसे लोगों की गवाही सामने आई जो प्रदर्शन स्थल पर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। वहां एक अनकही सामुदायिक भावना थी। अलग-अलग क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ खड़े थे। ये दृश्य हमें उस शांतिपूर्ण साथ रहने और भाईचारे की याद दिलाते हैं जो भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की पहचान है।

हास्य ने इतना बड़ी ऑनलाइन पहुंच बना ली कि व्यक्तिगत पीड़ा, चोट और गिरफ्तारियों जैसी कहानियां भी लोगों की फीड के सबसे ऊपर आने लगीं। इससे समाज का वह हिस्सा भी इस मुद्दे से जुड़ने लगा जो शायद पहले इस पर ध्यान नहीं देता। यही हास्य का असली काम है। यह एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करता है। जो कंटेंट बहुत भारी, बहुत राजनीतिक या इतना आसान होता कि लोग उसे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते, वही किसी ऐसे व्यक्ति की फीड तक पहुंच जाता है जो खुद को राजनीति से दूर मानता है।

मीम किसी खतरे की तरह महसूस नहीं होता। लोग उसे देखते हैं, शेयर करते हैं, हंसते हैं और उसी प्रक्रिया में यह भी समझ लेते हैं कि एक छात्र के साथ मारपीट हुई है। हास्य पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं है कि देश के लिए प्यार कम है।

हालांकि Gen Z ने हास्य का इस्तेमाल एक ऐसी सहजता के साथ किया है जो पहले कभी नहीं देखा गया, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ लंबे समय से कहते आए हैं कि हास्य सिर्फ प्रदर्शन को सजाने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह असली राजनीतिक काम करता है। 2017 के एक लेख में Marjolein;t Hart ने बताया कि कैसे हंसी ने 16वीं सदी के ऑग्सबर्ग से लेकर ग्दांस्क के सॉलिडैरिटी आंदोलन तक प्रदर्शनकारियों का साथ दिया। उन्होंने इसे सच में 'कमजोर लोगों का हथियार' बताया। व्यंग्य और हास्य ने प्रदर्शनकारियों को अपनी सामूहिक पहचान बनाने में मदद की और बड़े समाज के सामने अपने मुद्दे को रखने का तरीका दिया, यहां तक कि जब उन पर असली दमन हो रहा था। हाल के प्रदर्शन में इस्तेमाल किया गया रणनीतिक हास्य इंटरनेट से पहले के आंदोलनों में इस्तेमाल की जाने वाली पुरानी रणनीतियों की ही अगली कड़ी है। जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारियों ने बस इसका इंटरनेट वाली नई भाषा में इस्तेमाल खोज लिया।

कमेंट सेक्शन में दिखने वाली बेचैनी शायद इसलिए है क्योंकि पुरानी पीढ़ी विरोध के इन नए तरीकों को समझने में कठिनाई महसूस करती है। या फिर इसलिए क्योंकि कुछ लोग इस समय की गंभीरता को लेकर सच में चिंतित हैं। लेकिन सिर्फ इस वजह से आंदोलन को खारिज कर देना कि उसमें हास्य सबसे आगे दिखाई दे रहा है, असल बात को नजरअंदाज करना है। हास्य संदेश पहुंचाने का तरीका था, विश्वास की कमी नहीं। 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। क्या आखिरकार सत्ता को झुकाने का कारण गंभीरता नहीं, बल्कि यह प्रदर्शन और उसका तमाशाई अंदाज था?

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुप्रभात

तेरी यादों को इस तरह संभाल रखा है
खुद को मैने तेरे सांचे में ढाल रखा है

एक अरसा हुआ मिला नहीं हूं मैं खुद से
खुद को पूरी तरह खुद से निकाल रखा है

चौंक जाता हूं ज़रा सी किसी भी आहट पर
तेरे होने का भरम अब भी पाल रखा है

कभी तो याद किया होगा मुझे तुमने भी
किसी कोने में दिल के ये सवाल रखा है

मैं हूं तैयार ज़माने का ज़हर पीने को
और तुम हो कि अभी तक मलाल रखा है।

- आमोद 'अल्पज्ञ'

किसानों को वैज्ञानिक खेती और समृद्ध भविष्य से जोड़ने का जरिया है बलराम कृषि महोत्सव : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

किसान के खाते में पहुंचे एकमुश्त चार हजार रूपए

खण्डवा में होगी पुलिस बटालियन की स्थापना, मूंदी से खण्डवा रोड बनेगा शीघ्र

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने खंडवा जिला मुख्यालय में हुये बलराम कृषि महोत्सव में प्रदेश के 82 लाख 70 हजार से अधिक किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 3308 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से अंतरित किये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई उन्नत कृषि पर केंद्रित कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती-किसानी को लाभदायी बनाने और कृषि को आधुनिक स्वरूप देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव केवल एक आयोजन न होकर किसानों को नई तकनीक, वैज्ञानिक खेती और समृद्ध भविष्य से जोड़ने का व्यापक अभियान है। यह किसानों का अपना कार्यक्रम है, किसान इसका अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपनी खेती को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खंडवा की बात ही अलग है। अतीत का खानदेश अब कई खासियतों के लिए मशहूर है। यहाँ की काली मिट्टी फसलों के लिए सोने जैसी है। इसीलिए यहां की फसलें भी सोने के भाव बिकती हैं। खंडवा जिले के हर खंड में किसानों की मेहनत से खुशहाली है। बात खेती-किसानी की हो, या जल और पर्यावरण बचाने की, खंडवा हर मामले में अव्वल है।

बाहरी आडंबरों से अलग है दादाजी धूनीवाले धाम, जहां आध्यात्मिक शक्ति का होता है अनुभव : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि खंडवा के सुप्रसिद्ध धूनीवाले दादाजी का स्वभाव जनकल्याणकारी भावनाओं से ओत-प्रोत था। उन्होंने अपने जीवनकाल में सर्वधर्म सद्भाव, भूखों को अन्न खिलाने और श्रद्धा-भाव से सभी भक्तों के कष्टों के निवारण को प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री ने खंडवा में दादा धूनीवाले बाबा आश्रम में पूजा अर्चना की। बलराम कृषि महोत्सव में हल भेंट कर अभिनन्दन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दादाजी धूनीवाले धाम बाहरी आडंबर से अलग है और यहां आने के बाद हर किसी को आंतरिक और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है। बड़े दादाजी और छोटे दादाजी का यह अविस्मरणीय स्थान खंडवा ही नहीं, संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए गौरव और आस्था का स्थान रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को खंडवा जिला मुख्यालय में दादाजी धूनीवाले धाम में दर्शन-पूजन करने के बाद स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे।

- **किसानों के प्रति सरकार के मन में अगाध श्रद्धा और सम्मान-** मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार लगातार किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। किसान अपनी मेहनत और पसीने से धरती से अन्न उगाते हैं और भूखों को अनाज उपलब्ध कराते हैं। किसानों के प्रति हमारी सरकार के मन में अगाध श्रद्धा और सम्मान है। किसान भाइयों को आज एक साथ 4000 रुपए सम्मान निधि के रूप में उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं।
- **कृषक कल्याण वर्ष में किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प-** मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की क्षमताओं को पहचानती है। भारत वह देश है, जो अपनी परम्पराओं में वसुधैव कुटुम्बकम का भाव रखते हुए संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानता है। हमारी संस्कृति जियो और जीने दो पर विश्वास करती है। भगवान बलराम कृषि क्षेत्र के पहले देवता हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए हम वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसमें प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बलराम कृषि महोत्सव मनाये जा रहे हैं।
- **दुग्ध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य-** मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह किसानों के प्रति हमारी संकल्प शक्ति का ही परिणाम है कि आज प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़कर 65 लाख हैक्टेयर हो गया है, जो कि वर्ष 2002-03 से पहले मात्र 44 लाख हैक्टेयर था।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की बर्बरता सही नहीं

- सुप्रीम कोर्ट बोला-आंदोलन एक संवैधानिक अधिकार है

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, जिसे छीना नहीं जा सकता। केवल प्रदर्शन या

आंदोलन होने के आधार पर पुलिस की बर्बरता या सख्ती को सही नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने साथ ही कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले होना उतनी ही चिंता की बात है और सरकार से इस पर जवाब मांगा जा सकता है। अब कोर्ट मंगलवार को इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में आरोप है कि नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने ज्यादती की। ये याचिकाएं 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संसद मार्च से जुड़ी हैं।

एक और सुसाइड अब महाराष्ट्र की छात्रा ने दी जान

- जंतर-मंतर में सीजेपी आंदोलन के बाद आया पहला केस

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में 19 साल की मेडिकल छात्रा अंकिता सांगले ने रविवार को आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें

अंकिता ने लिखा कि परीक्षा में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलने से वह मानसिक तनाव में थी और डॉक्टर बनने का उसका सपना अधूरा रह गया। परिवार के मुताबिक घटना से पहले छात्रा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। काफी देर तक कमरे से कोई आवाज नहीं आने पर उसकी मां ने दरवाजा खोला, जहां वह मृत मिली। नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन खत्म हो गया था। प्रदर्शन खत्म होने के बाद सुसाइड का यह पहला मामला है। नीट मुद्दे पर अब तक 23 स्टूडेंट आत्महत्या कर चुके हैं।

अंकिता को री-एग्जाम में 166 मार्क्स मिले- अंकिता ने सुसाइड नोट में लिखा कि री-एग्जाम में उसे 166 मार्क्स मिले, जबकि कटऑफ 177 था। मेरे इस कदम के लिए उसके माता-पिता और भाई को जिम्मेदार न ठहराया जाए।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर 'सुप्रीम' आदेश

नई एसआईटी गठित सीए भी होगा सदस्य

नई दिल्ली (एजेंसी)। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच की सामने यूपी सरकार ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच के लिए एसआईटी का दुबारा गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों को अपनाते हुए नई गठित एसआईटी में वरिष्ठ अधिकारीयों को शामिल किया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) किरण एस को जांच विभाग का प्रमुख बनाया गया है। साथ ही तीन सदस्यीय एसआईटी में दो सीनियर आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनमें अयोध्या रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) सोमेन बर्मा और अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) गौरव ग्रोवर शामिल हैं।

नई एसआईटी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

इस नई गठित एसआईटी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि टीम में किसी चार्टेड अकाउंटेंट (सीए) को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि जल्द ही सीए को भी शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह एसआईटी में पांचवें सदस्य के तौर पर एक फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करे। यह टीम दो हफ्ते के अंदर अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद 25 जुलाई को जारी एक नोटिफिकेशन के जरिए एसआईटी का गठन किया गया था। बेंच ने सुनवाई को दो हफ्ते के लिए टालते हुए कहा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हम घटना की अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। सीजेआई ने कहा, हम निष्पक्ष, तेज और बिना किसी भेदभाव के जांच कराने पर ध्यान दे रहे हैं। 20 जुलाई को बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह एसआईटी बनाए।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20°c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 28 जुलाई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

दुबई-मुंबई इंडिगो फ्लाइट की राजकोट में इमरजेंसी लैंडिंग

● कार्गो कंपार्टमेंट से धुआं निकलने पर पायलट ने प्लेन उतारा

194 यात्री-क्रू सवार थे, हादसा टला, सभी यात्री सुरक्षित

अहमदाबाद (एजेंसी)। दुबई से मुंबई आ रही इंडिगो फ्लाइट की गुजरात के राजकोट में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, फ्लाइट में धुआं देखा गया था, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया गया। इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी मिलके ही राजकोट एयरपोर्ट अथॉरिटी तुरंत हाई अलर्ट पर आ गए। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आ गया। राजकोट एयरपोर्ट के रनवे पर इमरजेंसी सेफ्टी प्रोटोकॉल ऐक्टिव कर दिए गए हैं। इसके अलावा राजकोट फायर डिपार्टमेंट की कई गाड़ियां और पानी के टैंकर हवाई अड्डे के रनवे पर तैनात किए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस के आला आधिकारी सहित एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम भी एयरपोर्ट पर मौजूद है। इसी साल 5 मई को पंजाब के मोहाली स्थित शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइ लैंड होने के तुरंत बाद ही एक पैसेंजर के पावर बैंक में ब्लास्ट हो गया था। इससे पैसेंजर्स के बीच अफरातफरी मच गई थी। आनन-फानन में पैसेंजर्स को इमरजेंसी डोर से बाहर निकाला गया था। विमान में 198 यात्रियों और छह क्रू सदस्य शामिल थे। कुछ ही पलों में धुआं पूरे कैबिन में फैल गया था। अफरातफरी के बीच केबिन क्रू के सदस्यों ने आग पर तुरंत काबू पा लिया था जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस दौरान विमान के अंदर धुआं भरने और घबराहट के वजह से पैसेंजर्स में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी।

पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने में मेरा कोई रोल नहीं:गडकरी

● सड़क और परिवहन मंत्री बोले-यह पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ा

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने में उनका कोई रोल नहीं है। ये दोनों प्रोजेक्ट पूरी तरह से केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हैं। दरअसल मेटा प्लेटफॉर्म्स, एक्स और गूगल पर एथेनॉल मामले में गडकरी के कई सारे एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो वायरल हो रहे हैं। गडकरी ने याचिका में कहा है कि इन वीडियो में उन्हें एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) प्रोग्राम और ई20 पहल से गलत तरीके से जोड़ा गया है। गड़करी इससे नाराज हैं।

● **सरकारी मंत्रालयों को भी बनाया गया प्रतिवादी**– इस मामले में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा दूरसंचार मंत्रालय को भी प्रतिवादी बनाया गया है। गडकरी ने स्पष्ट किया है कि इस मुकदमे का उद्देश्य सार्वजनिक चर्चा या सरकारी नीतियों की आलोचना को रोकना नहीं है। याचिका में कहा गया है कि इसका मकसद जनता को किसी भी सरकारी फैसले पर निष्पक्ष बहस या आलोचना से रोकना नहीं है।

संक्षिप्त समाचार

‘शिक्षा, रोजगार और जवाबदेही’ बन सकते हैं प्राथमिकता

सीजेपी प्रोटेस्ट का दिल्ली की राजनीति पर होगा व्यापक असर

नई दिल्ली (एजेंसी)। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर शुरू हुआ युवाओं का आंदोलन केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद भले ही खत्म हो गया हो लेकिन इसका असर सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। जिस तरह दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के युवाओं ने इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, उसके बाद माना जा रहा है कि इसका दूरगामी असर दिल्ली की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। खासकर शिक्षा, रोजगार, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मुद्दे अब राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं में शामिल हो सकते हैं। **युवा वोटर्स को देखते हुए बदलनी पड़ सकती है चुनावी रणनीति**– इसकी एक बड़ी वजह दिल्ली में युवाओं की मजबूत चुनावी हिस्सेदारी भी है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली की वोटर लिस्ट में 18 से 29 साल के वोटर्स की हिस्सेदारी करीब 19 फीसदी है। इनमें 18 से 25 साल के युवाओं की संख्या लगभग 12 से 15 लाख के बीच है। यही वर्ग चुनावों में बढ़-चढ़कर वोट भी करता है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस आंदोलन के बाद युवा वर्ग सतर्क होगा।

एके-47 से फायरिंग करने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड

बिहार में एसपी के बॉडीगार्ड ने भीड़ की ओर चलाई थी गोलियां

सीवान (एजेंसी)। छात्रों पर लाठीचार्ज और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर 25 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया। इस दौरान पूरे प्रदेश में जमकर हंगामा और बवाल हुआ। 11 जिलों से पथराव और लाठीचार्ज की खबर आई। सबसे ज्यादा हंगामा सीवान में हुआ। जहां प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई। अब इस मामले में कार्रवाई हुई है, सीवान में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान एके-47 से फायरिंग करने वाले एसपी पूरन झा के बॉडीगार्ड अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। फायरिंग में तीन छात्रों को गोली लगी थी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जनहित याचिका दायर की है। मामले पर कल सुनवाई होगी। पूरे मामले पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा- पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। इधर, सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने कहा है कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान सीवान में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी।

भोपाल कूच पर निकले किसानों को रोका

40 नेता हिरासत में, प्रदर्शनकारी रिहाई की मांग पर अड़े, बोले- नेता छूटेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे

नर्मदापुरम/भोपाल (नप्र)। मूंग की शत-प्रतिशत खरीदी और खाद वितरण के लिए ई-टोकन व्यवस्था की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन सोमवार को निर्णायक दौर में पहुंच गया। नर्मदापुरम के सेठानी घाट से भोपाल के लिए निकले किसानों को शाम तक भोपाल चौराहे पर पुलिस ने रोक दिया।

किसान हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई की मांग पर अड़ गए। इस बीच कई घंटे नजरबंद रहने के बाद क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर सिंह राजपूत को रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी साथियों की रिहाई तक किसान आगे नहीं बढ़ेंगे।

भोपाल चौराहे पर रुका पैदल मार्च

दोपहर में सेठानी घाट से बड़ी संख्या में किसान नारेबाजी करते हुए पैदल भोपाल के लिए रवाना हुए थे। किसानों ने पहले ही ऐलान किया था कि रास्ते में बैरिकेडिंग मिली तो उसे तोड़कर आगे बढ़ेंगे। हालांकि, भोपाल चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया।

मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और प्रशासन व किसान नेताओं के बीच बातचीत शुरू हुई। एएसपी अभिषेक राजन ने बताया कि कलेक्टर और एसपी स्वयं किसान नेता लीलाधर सिंह राजपूत को लेकर मौके पर पहुंचे हैं।

रिहाई के बाद राजपूत बोले- सभी साथी आएंगे, तभी आगे बढ़ेंगे- सुबह से सर्किट हाउस में नजरबंद रखे गए क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर सिंह राजपूत को शाम को रिहा कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय दिया गया, फिर यह कहकर बैठक रद्द कर दी गई कि मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए हैं। राजपूत ने कहा कि सभी किसान नेताओं की रिहाई तक आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बैरिकेडिंग और पुलिस बल से किसानों की आवाज नहीं दबाई जा सकती।

40 किसान नेता हिरासत में, कई जगह बैरिकेडिंग- भोपाल कूच से पहले पुलिस-प्रशासन ने नर्मदापुरम, हरदा, इटारसी, डोलरिया, सिवनी मालवा और पिपरिया समेत कई जगह बैरिकेडिंग और चेकिंग की। हरदा में 25 और नर्मदापुरम में 14 किसान नेताओं व पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया या नजरबंद किया। हरदा में उन्हें अस्थायी जेल में रखा गया है।

नर्मदापुरम में कांग्रेस और किसान कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी नजरबंद किया गया।

पैसे लेकर काम न करने वाली संस्थाओं पर एक्शन ले केंद्र सरकार : भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष

किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत बनाने के लिए गठित क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज पर भारतीय किसान संघ ने गंभीर सवाल उठाए हैं। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष साई रेड्डी ने दावा किया कि देशभर में कार्यरत करीब 1000 सीबीबीओ में से लगभग 70 प्रतिशत अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से ऐसे सीबीबीओ की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें निरस्त करने की मांग की। भोपाल स्थित भारतीय किसान संघ के कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में साई रेड्डी ने कहा कि संघ ने इस विषय पर एक समिति बनाकर अध्ययन किया है। जांच में सामने आया कि कई सीबीबीओ ने एफपीओ को मजबूत बनाने और किसानों को व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने का काम अपेक्षित स्तर पर नहीं किया।

एंटी पेपर लीक संशोधन बिल लोकसभा में पेश

● पेपर लीक किया तो अब होगी 10 साल की जेल!

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया है। इसका मकसद पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा में होने वाली धांधली पर पहले से कहीं ज्यादा सख्ती करना है। प्रस्तावित कानून के तहत संगठित पेपर लीक के मामलों में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। साथ ही जांच और सुनवाई को भी तय समय में पूरा करने का प्रावधान किया गया है। जब देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर छात्रों का भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, यही कारण है कि यह बिल लाया गया। सरकार का कहना है कि ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए कानून को और मजबूत बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सख्त कार्रवाई, तेज जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट का भरोसा जता चुके हैं। इसके साथ ही एनटीए में तकनीकी सुधारों के सुझाव देने के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है।

● **जुर्माना बढ़कर 10 करोड़ रुपए तक**– बिल में आर्थिक सजा भी काफी बढ़ाई गई है। अब दोषियों पर अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा यदि पेपर लीक के कारण परीक्षा दोबारा करानी पड़े, तो उसका खर्च भी दोषियों से वसूला जा सकेगा। अब केवल प्रश्नपत्र लीक ही नहीं, बल्कि एआई की मदद से नकल, परीक्षा प्रणाली की हैकिंग, ऑनलाइन पेपर भेजना और साइबर धोखाधड़ी भी कानून के दायरे में आएगी।

● **केवल छात्र नहीं, एजेंसियां भी होंगी जिम्मेदार**–यदि परीक्षा कराने वाली एजेंसी, सर्विस प्रोवाइडर, तकनीकी कंपनी या कोई अधिकारी लापरवाही या मिलीभगत का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इससे पूरी परीक्षा व्यवस्था की जवाबदेही तय होगी। बिल में जांच एजेंसियों को ज्यादा अधिकार देने, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और फास्ट ट्रैक अदालतों में मामलों की जल्द सुनवाई का प्रावधान किया गया है। सरकार का मकसद है कि पेपर लीक के मामलों का जल्दी निपटारा हो और दोषियों को सजा मिले।

धनुष भी थलपति विजय की तरह राजनीति में लेंगे एंट्री !

इवेंट में भाषण के दौरान ‘जनता की भलाई’ का किया इशारा

चेन्नई (एजेंसी)। साउथ के स्टार एक्टर-डायरेक्टर धनुष ने एक बार फिर राजनीति में आने की अटकलों को हवा दी है। उन्होंने अपने फैन्स से कहा कि वे सिर्फ फिल्मों से जुड़े जश्न तक ही सीमित न रहें, बल्कि अपनी एकता का इस्तेमाल जनसेवा के लिए करें। फैन्स के आयोजित एक ब्लड डोनेशन कैंप में कही गई उनकी ये बातें वायरल हो गईं। इसके बाद कई लोग सोचने लगे कि क्या वह भी थलपति विजय के नक्शेकदम पर चल रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में राजनीति में कदम रखा और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। इस इवेंट में अपने फैन्स से बात करते हुए धनुष ने एकता की ताकत के बारे में बताया और उनसे अपील की कि वे जरूरतमंद लोगों की मदद करके समाज में बदलाव लाएं। उन्होंने कहा, इतने सारे लोग एक जगह जमा हुए हैं। इस तरह की एकता में बहुत ताकत होती है। हमें इस एकता को एक मकसद देना होगा। सिर्फऑडियो लॉन्च से काम नहीं चलेगा।

किसानों के भोपाल में प्रर्दशन को लेकर पुलिस ने किसान जिला अध्यक्ष, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष को घर से उठा लाई

सोहागपुर। किसानों के आन्दोलन से सरकार कितनी भयभीत हो गई। इसका नजारा सोहागपुर विधानसभा के ग्राम भटगांव में नागरिकों को देखने को मिला। जब नर्मदा नदी के तट पर बसे छोटे से कस्बे भटगांव में सायं सायं करती पुलिस की गाड़ियां पहुंची। यहां किसान संगठन टिकैत के जिला अध्यक्ष ठाकुर कृष्णकांत एवं भटगांव सरपंच एवं ब्लाक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुधीर ठाकुर को भी घर से उठा लाई। पहले दोनों को नवीन थाना परिसर में बैठाया गया।

इसके साथ ही कांग्रेस के जलज शर्मा को सोहागपुर को भी लाया गया। वहीं ग्राम पंचायत करनपुर सरपंच आजादसिंह ठाकुर को भी पुलिस लेकर थाने पहुंची।

बाद में स्थानीय विश्राम गृह में लेकर गई। इस घटनाक्रम की सूचना मिलते ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरगोविंद पूर्बिया, नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल , कांग्रेस नेता मंजेश ठाकुर, वकील देवान्शु शर्मा, ब्लाक मंडलम अध्यक्ष सुमित ठाकुर, मातृशक्ति युवक कांग्रेस महासचिव सुरेखा शाह, अखलेश पटेल आदि उनसे मिलने स्थानीय विश्राम गृह पहुंचे। श्री सुधीर ठाकुर ने इस प्रतिनिधि को बताया कि मूंग की शत-प्रतिशत खरीदी को शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने की प्रशासनिक कड़ी है।ऐसा लगता है कि यह शांतिपूर्ण आंदोलन को जैसे अंग्रेजी शासन कुचलती थी। ठीक वैसा ही किया जा रहा है। यह किसी मायने में उचित नहीं है। इधर भारतीय राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ श्री कक्का शर्मा के प्रांतीय उपाध्यक्ष सोहागपुर विधानसभा के ग्राम किवलारी निवासी केशरी सिंह पटेल ने बुधनी से फोन पर बताया कि हम लोगों का नर्मदापुरम् के सेठानी घाट से किसानों का जत्था भोपाल पहुंच कर मुख्यमंत्री निवास के घेराव का था। हमारे बहुत सारी भोपाल चल गए। हम बुधनी पहुंचे यहां पुलिस ने बेरेकिट लगा रखे हैं। हम बुधनी से वापिस सोहागपुर अपने ग्राम किल्लारी आ रहें हैं। प्रशासन एवं पुलिस ने रवैया अपनाया किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है।यह किसी भी मायने में उचित नहीं कहा जा सकता।

ग्राम भटगांव में पहुंचे पुलिस वाहन

सोहागपुर। नर्मदा तट पर बसे छोटे कस्बे में नागरिक उस समय अचंभित रह गए। जब सायं सायं करती पुलिस की गाड़ियां पहुंची। इससे ग्राम कानाफूसी होने लगी कि आखिर किस अपराधियों को पकड़ने पुलिस पहुंची है।जब ग्रामीणों को पता चला कि किसानों के आन्दोलन को लेकर देश के किसान संगठन टिकैत के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत ठाकुर एवं उनके अग्रज ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष सुधीर ठाकुर को लेने पहुंची है।तब कानाफूसी होने लगी कि यह आजाद भारत है या अंग्रेजी शासन। हालांकि ऐसी प्रशासनिक एवं पुलिस की कार्यवाही कहीं न कहीं भाजपा के वोट बेंक में सेंध लाएगी कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी।

राइट क्लिक

आंदोलनों की 'नई भाषा' भी रची जेन ज़ी के आक्रोश ने !

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क- 9893699939
ajaybokil@gmail.com

देश की राजधानी जंतर मंतर पर पेपरलीक को लेकर विरोध प्रदर्शन में जेन ज़ी (जनरेशन ज़ूमर्स) का विरोध प्रदर्शन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस आंदोलन में जेन ज़ी ने अपनी मांगों के साथ विरोध प्रदर्शन की नई भाषा, तेवर, तरीके ने भी सारे देश का ध्यान खींचा है। इसे लेकर पुरानी और परंपरावादी पीढ़ी में हैरानी और गहरी नाराजी भी है। क्योंकि आजतक देश में हुए अनेक आंदोलनों में भाषा और अभिव्यक्ति का वैसा स्वरूप कभी नहीं दिखा, जैसा कि इस आंदोलन में दिखाई पड़ा। जेन ज़ी जिस भाषा का प्रयोग अपना विरोध प्रकट करने के लिए कर रहे थे, वह निश्चित रूप से संस्कारी भाषा के पैरोकारों को गहरी चोट पहुंचाने वाला रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यही युवा पीढ़ी है, जिसे देश को आगे ले जाना है, क्या वह इसी भाषा, अभिव्यक्ति, तेवर, वेशभूषा और (कु) संस्कारों के साथ आगे जाएगी? कई लोग इसे जेन ज़ी द्वारा अपने नैतिक व भाषाई पतन और अश्लीलता को सामाजिक स्वीकृति दिलाने की कोशिशों के रूप में देख रहे हैं। संवाद की मर्यादा और भारतीय संस्कारों को दरकिनार करने की बात भी हो रही है। यह सोच रखने वाली पीढ़ी मुख्यतः बेबी बूमर्स और मिलेनियल्स की है। जिनके लिए पारिवारिक संस्कार और शिक्षा पहले थी, तकनीकी सुविधा और डिजीटल दुनिया बाद में। लेकिन इस पीढ़ी को अहसास ही नहीं है कि 21वीं सदी में इंटरनेट, बेलगाम सोशल मीडिया और डिजीटल विश्व के असीमित विस्तार में जन्मी और पली बढ़ी-पीढ़ी एक अलग माहौल में तैयार हुई है, जिसमें पारंपरिक बातों का महत्व शून्य भले न हो, लेकिन न्यून जरूर है। आपसी रिश्तों और सामाजिकता को देखने-परखने का पैमाना अलग है। उदाहरण के लिए जंतर मंतर के इस प्रदर्शन में भी कई लड़कियां हाथों में ऐसे प्लेकार्ड्स लिए मस्ती के साथ घूमती दिखाई दीं, जिसे पारंपरिक अर्थ में अत्यंत अश्लील और अभद्र कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनका सभ्य समाज में उच्चारण भी अस्वीकार्य है। लेकिन उन लड़कियों के चेहरों पर इस बात की रत्तीभर चिंता नहीं दिखी कि ये प्लेकार्ड्स देखकर उनके अपने परिजन क्या सोच रहे होंगे, समाज में उनकी इज्जत क्या रह जाएगी, क्योंकि यह प्रदर्शन तो सार्वजनिक था हर पल की रिकॉर्डिंग किसी न किसी रूप में हो रही थी। ज्यादातर अश्लील प्लेकार्ड्स प्रधानमंत्री मोदी को निशाना साधते हुए बनाए गए थे। यह व्यवस्था और सत्ताधारियों के प्रति युवाओं का आक्रोश था, लेकिन मानसिकता अलग थी। इन प्लेकार्ड्स को लेकर भी अलग-अलग तर्क सुनाए दिए। शालीनता और मर्यादा के हामी लोगों ने इसे वामपंथी सोच से जोड़ा तो जवाब में यह दलील भी आई कि बीते 12 सालों (मोदी राज में) में युवाओं ने यही सब कुछ सीखा है। यह तो उसकी बानगी भर है।

सुंदर, संस्कारित भाषा, गालीगलौज वाली गंवई भाषा और तकनीकी भाषा जैसे विवादों से अलग केवल जेन ज़ी की भाषा की ही बात करें तो यह ट्रेंड वैश्विक है। जेन ज़ी बोले तो वो पीढ़ी जो 1997 से लेकर 2012 के बीच जन्मी, पली बढ़ी है। ये जब पैदा हुई तब इंटरनेट ने भारत में दस्तक दे दी थी और बाद में स्मार्ट फोन भी आ गए थे। लिहाजा इस पीढ़ी ने जवां होती डिजीटल और तकनीकी दुनिया में ही आंखें खोली और उसी में अपने सपने बुने, सहेजे। यह उनके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं।

इन युवाओं की जीवन शैली में तकनीकी और अल्गोरिदम के बढ़ते घालमेल ने एक नई भाषा को जन्म दिया, जो आज जेन ज़ी की अभिव्यक्ति और संवाद की भाषा बन गई है। ऐसी भाषा, जो शब्दों के संक्षिप्तीकरण, उनके अंकीकरण, प्रचलित अर्थ से अलग भाव बोध कराने, सांकेतिक रूप से उपयोग की जाती है। यानी एक ने कही, दूजे ने बूझी। इस भाषा पर अंग्रेजी का बहुत ज्यादा प्रभाव है, जो हिंदी जैसी समावेशी भाषा के भी शुद्धिकरण के पैरोकारों के लिए बड़ा झटका है। यह भाषा के सनातन आग्रह से भी बिल्कुल अलग है। इस भाषा में विभिन्न भाषाओं, अंकों, लिपियों और शब्दों के अर्थप्रवाह के भेद मिटते दिखाई देते हैं और शब्दों के पारंपरिक अर्थों की जगह नए अर्थ और संदर्भ रूढ़ होते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल अजूबा हैं।

जेन ज़ी की यह भाषा भी दो तरह की है। पहली है नेटस्पीक। नेट स्पीक इंटरनेट पर कुछ संशोधन के साथ प्रचलित मोटे तौर पर पारंपरिक भाषा ही है। लेकिन दूसरी और युवाओं में लगातार लोकप्रिय हो रही भाषा है- लेट अथवा लीटस्पीक। लेटस्पीक का एक अर्थ 'चलो बोलें' भी है। इस भाषा का उद्भव 1980 के दशक में बुलेटिन बोर्ड सिस्टम (BBS) में हुआ, 'एलीट' (श्रेष्ठ) का दर्जा प्राप्त करने से उपयोगकर्ता को फाइल, फोल्डरों, गेम और विशेष चैट रूम तक पहुँच मिलती थी। इस भाषा की शुरूआत दरअसल हैकरों और गमर्स ने की थी ताकि संवाद की गोपनीयता बनाई रखी जा सके। ऐसे शब्दों को गढ़ने का श्रेय 'कल्ट ऑफ द डेड काउ' हैकर समूह को जाता है। इस अर्थ में लेटस्पीक का लिखा जाना भी अलहिदा है। इसे अंकीय भाषा में 1337 लिखा जाता है। क्योंकि इसमें अंग्रेजी के T की शक्ल अंग्रेजी के ही अंक 7 से मिलती है। इसी तरह अंग्रेजी के E का अर्थ 3 तथा L का संकेत 1 से है। इसीलिए '1337'' को नई पीढ़ी 'लेटस्पीक' पढ़ती है। यहां संख्याओं का प्रयोग अक्षरों की समानता के आधार पर किया जाता है, और यह लेटस्पीक की दृश्य रचनात्मकता का एक हिस्सा है। ज्यादातर संदेश और जवाब इसी शैली में दिए जाते हैं। लिहाजा लेटस्पीक का ज्ञान रखने वाले ही इसे समझ सकते हैं। लेकिन जेन ज़ी इस भाषा में सहजता से संवाद करती है। यहां भाषा के संयम और सौंदर्य की जगह सुविधा और सम्प्रेषणीयता ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा की शीलता-अश्लीलता का भाव गौण है। जेन ज़ी की शब्दावली के कुछ नमूने इस प्रकार हैं- मसलन फैम (फैमिली) यानी परिवार और दोस्त यानी 'ब्रो।' 'ग्लो अप' यानी बुरे से अच्छे में बदलाव, 'सीईओ' यानी आपने सम्बन्धित विषय में महारत हासिल कर ली है। इसे भी संक्षेप में 'प्रो' कहा जाता है। 'कैंसल कल्चर' यानी किसी व्यक्ति या संगठन और विचारों को शर्मसार करना, 'स्टैन' अर्थात आप जुनूनी हैं लेकिन डरावने तरीके से नहीं, 'लिविंग रेंट फ्री' यानी ऐसी बात, जिसके बारे में आप सोचना बंद नहीं कर सकते, ' डब्ल्यू' का जेन ज़ी के लिए अर्थ जीत है। इसी प्रकार 'डैंक' यानी बहुत उच्च गुणवत्ता वाली चीज, 'घोस्टिंग' अर्थात किसी से रिलेशनशिप में रहने के बाद उसे अनदेखा करना, 'कैप' यानी झूठ बोलना और 'सॉल्टी' (नमकीन) का जेन ज़ी के लिए अर्थ है जलन महसूस करना, वगैरह। यह सूची लंबी हो सकती है। अब तो बाजार में लेटस्पीक कन्वर्टर भी आ गए हैं।

इस विरोध प्रदर्शन ने विरोध की भाषा और भावी दिशा की नई इबारत भी लिख दी। पहले नारों में जोश, आक्रोश, निराशा, कटाक्ष ही झलकते थे। कभी-कभी वह अभद्रता को स्पर्श करते भी लगते थे। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में युवा अपना रोष सोशल मीडिया पर मीम्स, रील्स, प्लेकार्ड्स, स्टिकर्स और जीआईएफ के जरिए व्यक्त कर रहे थे। इनमें भी आक्रोश, कटाक्ष है, लेकिन भाषा की मर्यादा का कोई तटबंध नहीं है। जो नारे सुनाई दिए उनमें कई तो प्रभावशाली थे, लेकिन कुछ नारे जो कानों को भद्दे और अश्लील लगे, वो इन युवाओं के लिए बिल्कुल 'सहज' दिखाई दिया। यह संस्कारों की परिभाषा का भी 'शिफ्ट' है, जो हमारी परंपरागत सोच से मेल नहीं खाता। जो लोग सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले रील्स, मीम्स, वीडियो और स्टैण्ड अप कॉमेडी वीडियो में जेन ज़ी द्वारा धड़ल्ले से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को जानते हैं, उन्हें पता है कि उसमें 'वर्जित' जैसा कुछ भी नहीं होता । जो परोक्ष था, वह प्रत्यक्ष बन गया है। अश्लील जोक्स पर लड़कियां भी ठहाके लगाती हैं और गंदी गालियों के मामले में भी पुरूषों के एकाधिकार को सहजता से तोड़ती दिखीं। यह बदलते समाज में नारी स्वतंत्रता और स्वावलंबन का नया पहलू है। यानी जो लड़कों के लिए 'मान्य' है, वो सब हमारे लिए भी मान्य होना चाहिए। लैंगिक समता और समानता का यह अपेक्षाकृत नया मूल्य है। यही कारण है कि अत्यंत अश्लील और खासकर भारतीय भाषा-बोलियों में स्त्री-पुरूष जननांगो और लैंगिक विभेद पर केन्द्रित गालियां भी जेन ज़ी धड़ल्ले से देने में संकोच नहीं कर रही हैं। धूम्रपान, सुरापान और ड्रग्स अब असामान्य बात नहीं है, वेशभूषा, केशभूषा और खानपान की मर्यादा भी टूट रही हैं तो भाषा और सामाजिक आचरण में उसका व्यक्त होना स्वाभाविक ही है, भले ही हम संस्कारों की कितनी ही माला जपते रहें। गलत अर्थ में ही सही, स्त्री-पुरूष भेदभाव के परे जीवन शैली की 'यूनिफार्मिटी' का यह आग्रह है, जो कहीं कोडिफाइड न हो, लेकिन युवाओं में सहज मान्य है। इस भाषा, इस तेवर की अभिव्यक्ति की कल को साहित्य और कलाओं में किस रूप में होगी, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन पारंपरिक मूल्यों और मानकों से काफी अलग होगी, यह तय है।

इसका अर्थ यही नहीं कि समूची जेन ज़ी ही ऐसी है, लेकिन जो दिख रहा है, वह बढ़ता ट्रेंड है, जो लीक अथवा परंपरा से हटकर जीने में, मान्य मूल्यों के प्रति बगावत करने और अपनी सोच समझ और दृष्टि को ही सही मानने के आग्रह से उपजा है। इसे संस्कार के डंडे से रोका जा सकता है, यह खाम खयाली अथवा पुरानी दुनिया में जीते रहने की जिद से ज्यादा कुछ नहीं है।

भाजपा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की शिकायत

भाजपा ने जीतू पटवारी के दतिया में प्रचार पर रोक लगाने की मांग की

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के दतिया विधानसभा उपचुनाव के दौरान दिए गए बयान को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शिकायत दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखित शिकायत में कहा है कि जीतू पटवारी ने चुनावी सभा के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं शासकीय संस्थाओं पर तथ्यहीन और तर्कहीन आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने इन आरोपों को निराधार, भ्रामक और अत्यंत आपत्तिजनक बताते हुए कहा गया है कि इस प्रकार के बयान से न केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास हैं, बल्कि शासकीय संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी अनावश्यक प्रश्नचिह्न लगाते हैं। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जीतू पटवारी के बयान से मतदाताओं के बीच भ्रम और तनाव की स्थिति उत्पन्न होने के साथ-साथ दतिया में कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि श्री पटवारी का बयान आदर्श आचार संहिता की भावना के विपरीत है और चुनावी माहौल को प्रभावित करने वाला है। इसलिए निर्वाचन आयोग से मांग की गई है कि मामले की तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा चुनाव प्रचार की शेष अवधि के लिए श्री जीतू पटवारी के दतिया विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश एवं चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि मतदाता निर्भय एवं शांतिपूर्ण वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

जबलपुर के किशोर आर्यव श्रीवास्तव एआई विशेषज्ञ

भोपाल। जबलपुर से जुड़े 15 वर्षीय प्रतिभाशाली छात्र आर्यव श्रीवास्तव ने कम उम्र में ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स, विज्ञान और संगीत के क्षेत्र में कनाडा में अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी है। हाल ही में उनके द्वारा लिखे गए शोधपरक लेख में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित कम लागत वाले रोबोटिक समाधान की अभिनव अवधारणा प्रस्तुत की है, जिसका उद्देश्य नदियों, झीलों और बंदरगाहों से माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को प्रभावी ढंग से हटाना है। आर्यव ने इस परियोजना का कार्यशील मॉडल तैयार कर ओंटारिओ में राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया और अपने राज्य का राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता में अलबर्टा में प्रतिनिधित्व किया। उल्लेखनीय है कि वे विगत वर्ष भी राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं। उनकी यह उपलब्धि उनकी वैज्ञानिक सोच, इनोवेशन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

आर्यव केवल एक उभरते हुए आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स उत्साही ही नहीं, बल्कि एक मान्यता प्राप्त पियानो वादक भी हैं। तकनीक, संगीत और रचनात्मक सोच का यह अनूठा समन्वय उन्हें अपनी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है। इन दिनों आर्यव अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताने जबलपुर आए हुए हैं। उनके नाना-नानी सुशील दीवान एवं सुमन दीवान आज भी जबलपुर में निवास करते हैं। उनके दादा प्रसिद्ध व्यंग्यकार समीर लाल, जो वर्तमान में कनाडा में रिस्क मेनेजमेंट एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स गवर्नेंस के विशेषज्ञ, लेखक एवं अंतरराष्ट्रीय वक्ता हैं, कनाडा जाने से पूर्व जबलपुर में एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। इसी कारण परिवार का जबलपुर से संबंध बना हुआ है।

29 साल की मेकअप आर्टिस्ट से रेप

घुमाने के बहाने होटल ले गया, शादी का वादा कर किया दुष्कर्म, केस दर्ज, आरोपी फरार

भोपाल (नप्र)। भोपाल के रातीबड़ इलाके में मेकअप आर्टिस्ट से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, इसके बाद वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने जल्द शादी करने का भरोसा पीड़िता को दिलाया था। अब युवक ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। तब पीड़िता थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज करा दी। टीआई रास बिहारी शर्मा के मुताबिक, 29 वर्षीय युवती मेकअप आर्टिस्ट है। करीब एक महीने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी पहचान रोहित परमार से हुई थी।

वीडियो सोशल मीडिया में साझा किया, कहा- आदिवासियों का शांतिपूर्ण सत्याग्रह भी कुचला जा रहा

राहुल गांधी ने केन-बेतवा प्रभावितों की लड़ाई को दिया समर्थन

भोपाल (नप्र)। कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से प्रभावित किसानों और आदिवासियों के आंदोलन का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना के कारण आदिवासियों की जमीन तो ले ली गई, लेकिन उन्हें न न्यायपूर्ण मुआवजा मिला और न ही सम्मानजनक पुनर्वास।

सरकार सत्य और सत्याग्रह दोनों से डरती है

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सत्य और सत्याग्रह, दोनों से मोदी सरकार डरती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई-बहन अपनी मांगों को लेकर जल सत्याग्रह और भूख हड़ताल पर बैठे थे, क्योंकि केन-बेतवा परियोजना में उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई, लेकिन उनके अधिकारों की अनदेखी की गई।

सरेराह युवक की चाकू गोदकर हत्या

- पेट, सीने और पीठ पर ताबड़तोड़ वार; भाई बोला- पत्नी पर बुरी नजर रखता था आरोपी

भोपाल (नप्र)। भोपाल के गौतम नगर इलाके में रविवार की रात पारिवारिक रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। घर के पास कलारी के सामने 25 वर्षीय युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ चार वार कर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में तीन टीमें लगाकर दबिश दे रही है।

मृतक की पहचान सचिन पंथी (25) पुत्र मुकेश पंथी, निवासी गणेश मंदिर के पास, अटल अयूब नगर, थाना गौतम नगर के रूप में हुई है। वह चौक बाजार की एक क्रॉकरी दुकान में सेल्समैन था। परिवार में पांच भाई और एक बहन हैं, सचिन तीसरे नंबर पर था।

मृतक के भाई छोटू का आरोप है कि हत्या करने वाला राकेश पंथी, जो रिश्ते में मृतक की बुआ का बेटा है, लंबे समय से परिवार की महिलाओं पर गलत नजर रखता था। खासकर मेरी पत्नी पर वह लगातार अशोभनीय टिप्पणियां करता था। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ता गया।

कलियासोत डैम के कैचमेंट में अवैध मड रेस, बिना सुरक्षा के होता है आयोजन; दो गाड़ियों में हुई टक्कर

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलियासोत और केरवा डैम के कैचमेंट एरिया में अवैध मड रेस का आयोजन किया जाता है। कैचमेंट में एरिया में आयोजित मड रेस में दर्जनों गाड़ियों आती हैं। साथ ही देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ती है। इस आयोजन के लिए प्रशासन की कोई अनुमति नहीं होती है। न ही वहां पर सुरक्षा के इंतजाम होते हैं।

मड रेस का आयोजन- रविवार को छुट्टी का दिन था। इस दिन भी कैचमेंट एरिया में मड रेस का आयोजन शाम को करीब 3 बजे के बाद किया गया था। मड रेस में शामिल होने के लिए दर्जनों प्रतिभागी अपनी गाड़ियों को लेकर पहुंचे थे। साथ ही इस रोमांचकारी आयोजन को देखने के लिए शहर के लोग भी बड़ी संख्या में आए थे। मगर प्रशासन को इसकी खबर नहीं थी। बताया जा रहा है कि ऐसे आयोजन वहां हमेशा होते हैं।

दो गाड़ियों में हो गई टक्कर

वहीं, मड रेस के आयोजन के दौरान दो गाड़ियों में टक्कर हुई है। एक बड़ी गाड़ी से जिप्सी टकरा गई। टक्कर के बाद जिप्सी के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। न ही प्रशासन को खबर थी। टक्कर के बाद वहां मौजूद लोग गाड़ियों के करीब पहुंच गए। फिर देखने लगे कि चालक को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है न।

इको सिस्टम से खिलवाड़- दरअसल, कलियासोत डैम के कैचमेंट एरिया में इस तरह के आयोजन इको सिस्टम से खिलवाड़ है। हर वीकेंड पर यहां नियमों से खिलवाड़ होता है। लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में बाइक ले जाकर स्टंट करते हैं। वीकेंड के मौके पर कैचमेंट एरिया में भारी भीड़ उमड़ती है।

मालिक के साथ थमी थीं डुग्गू की सासें, अब दोनों को एक साथ दी गई श्रद्धांजलि

अटूट है इंसान और जानवर की प्रेम कहानी

बैतूल (नप्र)। कभी-कभी कुछ रिश्ते खून के नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और निःस्वार्थ समर्पण से बनते हैं। बैतूल में इंसान और उसके पालतू साथी के ऐसे ही अटूट रिश्ते ने पूरे शहर को भावुक कर दिया। 15 वर्षों तक अपने मालिक का साया बनकर रहने वाले पालतू डॉगी डुग्गू ने अपने मालिक प्रदीप जीवनधर जैन (67) का साथ अंतिम सांस तक निभाया। अब इस अनोखे रिश्ते को याद करते हुए शहर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हर आंख नम दिखाई दी। मालिक और डॉगी के अंतिम सफर की इस कहानी ने सभी शहरवासियों को भावुक कर दिया। सभी ने नम आंखों से दोनों को पुष्पांजलि अर्पित की।

दोनों को एक साथ अर्पित किए श्रद्धासुमन

रविवार को बैतूल स्थित राधाकृष्ण धर्मशाला में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में परिवारजन, रिश्तेदार, समाज के वरिष्ठजन, मित्र एवं बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम में केवल प्रदीप जैन को ही नहीं, बल्कि उनके वफादार साथी डुग्गू को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

- **अंतिम सांस तक दिया साथ-** कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उस मार्मिक घटना को याद किया जिसने पूरे बैतूल को भावुक कर दिया था। प्रदीप जैन का भोपाल स्थित एम्स अस्पताल में उपचार के दौरान निधन होने के बाद जब उनका पार्थिव शरीर बैतूल लाया गया, तब डुग्गू पूरी रात उनके पास बैठा रहा। वह बार-बार अपने मालिक को निहारता रहा, मानो उन्हें उठने का इंतजार कर रहा हो। जब अंतिम यात्रा निकली तो डुग्गू भी अर्थी के पीछे-पीछे चलता हुआ श्मशान घाट तक पहुंचा। वहां कुछ देर अपने मालिक के पास शांत बैठा रहा और फिर उसने भी वहीं अंतिम सांस ले ली। इस दृश्य को जिसने भी देखा, उसकी आंखें भर आईं।
- **प्रेम की मिसाल बना यह रिश्ता-** श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में जहां रिश्तों में स्वार्थ और दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वहीं डुग्गू ने अपनी वफादारी से यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी भाषा या शब्दों का मोहताज नहीं होता।

मूंग खरीदी पर केंद्र-एमपी सरकार आमने-सामने

देश का 87 प्रतिशत कोटा एमपी से... फिर भी प्रदेश में सिर्फ 2 फीसदी खरीद हुई, लेटर वॉर छिड़ा

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। नर्मदापुरम्, सीहोर, रायसेन, हरदा और आसपास के जिलों में किसान समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होने से नाराज हैं। इसी बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि प्रदेश को देश में सबसे अधिक मूंग खरीदी का कोटा पहले ही दिया जा चुका है।

इसके बावजूद राज्य सरकार अब तक स्वीकृत मात्रा का महज 2 प्रतिशत ही खरीद सकी है। ऐसे में पहले स्वीकृत लक्ष्य पूरा करने के बाद ही अतिरिक्त कोटे पर विचार किया जाएगा।

तीन दिन पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भेजे गए पत्र में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि मुख्यमंत्री ने 21 मई 2026 के अपने लेटर के माध्यम से मूंग खरीदी की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसके जवाब में केंद्र ने खरीद के नियमों और प्रदेश की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की है।

16 जुलाई तक सिर्फ 7,947 टन खरीदी- केंद्र सरकार ने पत्र में कहा है कि 16 जुलाई 2026 तक राज्य में केवल 7,947.92 मीट्रिक टन मूंग की खरीद हो सकी है। इससे लगभग 12 हजार किसानों से ही उपज खरीदी गई, जबकि यह स्वीकृत मात्रा का मात्र 2 प्रतिशत है। केंद्र ने राज्य सरकार से पहले मंजूर मात्रा की खरीदी तेजी से पूरी कराने को कहा है। एमपी में मूंग खरीदी का कोटा 4,54,580 मीट्रिक टन है। 16 जुलाई तक मात्र दो फीसदी ही मूंग खरीद हुई है।

कोटा पूरा होने के बाद ही बढ़ेगी सीमा- शिवराज सिंह चौहान ने पत्र में स्पष्ट किया है कि पीएसएस (मूल्य समर्थन योजना) के दिशा-निर्देशों के तहत तूर, उड़द और मसूर की 100 प्रतिशत खरीद के अलावा अन्य अधिसूचित फसलों की खरीद अनुमानित उत्पादन के अधिकतम 25 प्रतिशत तक ही की जा सकती है। इसलिए पहले स्वीकृत मात्रा की खरीद पूरी होने के बाद ही अतिरिक्त मात्रा की मंजूरी के प्रस्ताव पर नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।

इधर किसान आंदोलन तेज, भोपाल तक पदयात्रा

मूंग खरीदी समेत कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश ने 27 जुलाई से नर्मदापुरम् के सेठानी घाट से किसान क्रांति पदयात्रा शुरू करने की घोषणा की है। पदयात्रा बुधनी, बरखेड़ा, ओबेदुल्लागंज और मंडीदीप होते हुए 29-30 जुलाई को भोपाल पहुंचेगी। किसानों की योजना मिसरोद, बाग सेवनिया, रानी कमलापति, बोर्ड ऑफिस, रोशनपुरा और पॉलीटेक्निक चौराहे से होते हुए मुख्यमंत्री निवास तक मार्च निकालने की है। किसान अपने साथ ट्रैक्टर, पिकअप और अन्य वाहनों में भोजन व दैनिक उपयोग की सामग्री भी लेकर चलेंगे।

किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं हुई या मांगों पर संतोषजनक निर्णय नहीं निकला तो भोपाल में चक्काजाम किया जाएगा। साथ ही ओबेदुल्लागंज से मिसरोद के बीच रेल मार्ग बाधित करने की भी संभावना जताई गई है।

संपादकीय

क्रियान्वयन कब होगा?

पेपरलीक को लेकर दिल्ली में महीना भर चले जेन ज़ी आंदोलन का असर अब दिखाई देने लगा है। इस पूरे मामले में मोदी सरकार तेजी से एक्शन में दिखाई दे रही है। पहले सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डॉ.धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया और अब परीक्षा प्रणाली में ठोस सुधार की नीयत से उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स बनाया है, जिसका प्रमुख जाने माने आईटी विशेषज्ञ और इंफोसिस के सह संस्थापक रहे नंदन नीलकेणि को बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया नीलकेणी टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर ही परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। पीएम ने इस मामले में सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों के बारे में कहा कि जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है वे जेलों में सड़ रहे हैं। हम फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल भी पार्लियामेंट में कठोर कानूनी प्रावधानों के साथ नया क़ानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति भरोसेमंद हो, पारदर्शी हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक हाई पावर्ड टास्क फ़ोर्स बनाने का फ़ैसला किया गया है। नीलकेणी के अतिरिक्त इस टास्क फोर्स में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस. सोमनाथ, आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी. कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा को भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि नंदन नीलेकणी की पहचान सफलता, संपत्ति, सूचना और कॉरपोरेट स्टाइट के प्रतीक के तौर पर रही है। उनके फ़ैसले मीडिया की सुर्खियां बनते रहे हैं। पूर्व में यूपीए की डॉ. मनमोहन सिंह सरकार ने नीलकेणी के नेतृत्व में ही 'आधार कार्ड' की योजना शुरू की थी, जिसे बाद में मोदी सरकार ने अनिवार्य बनाया। बाद में नंदन नीलकेणी ने 2014 में कांग्रेस के टिकट पर बेंगलुरु साउथ लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो मोदी लहर में बीजेपी के अनंत कुमार से हार गए थे। नीलकेणी हाल के दिनों में पर्यावरण और बायो डायवर्सिटी के मुद्दों पर काफी सक्रिय रहे हैं। उधर कांग्रेस ने मोदी सरकार द्वारा परीक्षा सुधार के लिए बनी इस हाई पावर्ड कमेटी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इसके पूर्व मोदी सरकार ने जून 2024 में नीट-यूजी समेत कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के बाद, मोदी सरकार ने परीक्षाओं के 'पारदर्शी, सुचारु और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने' के लिए डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। अब फिर सरकार ने नीलकेणी की अध्यक्षता में नई कमेटी बनाई है। सरकार राधाकृष्णन कमेटी की 101 सिफारिशों को ही लागू नहीं कर पाई है। यहां तक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाली एनटीए में अभी तक पूर्णकालिक महानिदेशक तक नहीं है। उधर संसद में भी विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। यहां सवाल यह है कि क्या सरकार सचमुच पेपर लीक जैसी अत्यंत गंभीर समस्या का कोई समाधान खोजना चाहती है या फिर केवल कमेटियां बनाकर छात्रों और आम जनता को भुलावे में रखना चाहती है? असल सवाल क्रियान्वयन का है। प्रश्न यह भी है कि नीलकेणी फोर्स की सिफारिशें आने के बाद राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों का क्या होगा? या दोनों की सिफारिशों की आधार पर सरकार कोई कार्रवाई करने वाली है, यह अभी अस्पष्ट है। मूल मुद्दा तो इन संस्थाओं में नैतिक रूप से ईमानदार लोगों को बैठाने का है, जिसकी कहीं बात नहीं हो रही है।

नजरिया

संजय सक्सेना

लेखक लखनऊ निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

लोकतंत्र शोर नहीं, सख्त सवालों से होगा परिपक्व

समय के साथ लोगों की सोच और नजरिया काफी बदल गया है। खासकर आज की युवा पीढ़ी में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बदलाव की वजह सोशल मीडिया और मोबाइल है, जिसमें सब कुछ खुला हुआ है। डिजिटल क्रांति और 24/7 न्यूज चैनलों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस युग में सुकरात और कौटिल्य जैसे विचारकों को ज्ञान और अनुभव के वर्षों बाद सम्मान मिलता था, आज रील्स और ट्वीट्स के 15 सेकेंड में हर इंसान खुद को महाज्ञानी घोषित कर चुका है। लेकिन इस पूरे तमाशे का सबसे विकृत पहलू यह है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ (मीडिया) और सोशल मीडिया के दौर ने देश के खारिज किए गए नेताओं को एक ऐसा मुफ्त का लाउडस्पीकर दे दिया है, जो बिना किसी जवाबदेही के दिन-रात बजता रहता है। जनता जिन्हें चुनाव में नकार देती है, जिन्हें जमीन पर दो लोग सुनने को तैयार नहीं होते, वही नेता शाम 8 बजे टीवी स्क्रीन पर आकर देश और दुनिया को नैतिकता और शासन का पाठ पढ़ाते हैं। मीडिया उन्हें रहनुमा की तरह पेश करता है, लंबी-लंबी बाइट्स दिखाता है, लेकिन अफसोस, उनसे एक तीखा या सही सवाल पूछने का साहस कोई पत्रकार नहीं जुटा पाता।

आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकारिता का धर्म निभाने के बजाय पौराणिक नारद मुनि की भूमिका में आ चुका है, लेकिन एक नकारात्मक अर्थ में। मीडिया का काम अब सच उजागर करना नहीं, बल्कि दो नेताओं को स्टूडियो में आमने-सामने बिठाकर उनमें आग लगाना रह गया है। देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, कृषि और वैज्ञानिक विकास जैसे बुनियादी मुद्दे अब गौण हो चुके हैं। मीडिया के लिए वही खबर प्राइम टाइम के लायक है, जो समाज में सनसनी फैलाए या नफरत का तड़का लगाए। जब कोई खारिज किया गया नेता स्टूडियो में बैठकर बेतुके दावे करता है, तो एंकर उनसे यह नहीं पूछता कि आपने अपने कार्यकाल में इस समस्या के लिए क्या किया? या जनता ने आपको क्यों हराया? इसके बजाय, एंकर सिर्फ एक पक्ष के नेता का बयान दूसरे के सामने उछालकर बहस को गाली-गलौज का मंच बना देता है।

सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के इस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि मीडिया का पूरा ध्यान या तो वंशवादी-विरासती राजनीति के राजकुमारों पर रहता है, या फिर रोज बखेड़ा खड़ा करने वाले ट्रोल-नेताओं पर। इस तमाशे के बीच वे नेता पूरी तरह अनदेखा कर दिए जाते हैं, जो किसी राजनीतिक घराने से नहीं आते, बल्कि अपनी शिक्षा, जमीनी संघर्ष और कार्य-योग्यता के बल पर आगे बढ़े हैं। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। डॉ. एस. जयशंकर किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते। वे एक पूर्व नौकरशाह और कूटनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने अपनी प्रशासनिक और बौद्धिक क्षमता के बल पर देश की विदेश नीति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जब वैश्विक मंचों पर भारत का रुख तय करने की बात आती है, तो जयशंकर जैसे योग्य नेताओं की नीतिगत बातें 2 मिनट के क्लिप में सिमट जाती हैं। वहीं दूसरी ओर, चुनाव हारे हुए नेता जब विदेश नीति पर कोई बचकाना बयान देते हैं, तो मीडिया उस पर 2 घंटे का प्राइम टाइम डिबेट चलाता है। योग्यता को दरकिनार कर सनसनी को तरजीह दी जाती है।

सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के इस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि मीडिया का पूरा ध्यान या तो वंशवादी-विरासती राजनीति के राजकुमारों पर रहता है, या फिर रोज बखेड़ा खड़ा करने वाले ट्रोल-नेताओं पर। इस तमाशे के बीच वे नेता पूरी तरह अनदेखा कर दिए जाते हैं, जो किसी राजनीतिक घराने से नहीं आते, बल्कि अपनी शिक्षा, जमीनी संघर्ष और कार्य-योग्यता के बल पर आगे बढ़े हैं। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। डॉ. एस. जयशंकर किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते। वे एक पूर्व नौकरशाह और कूटनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने अपनी प्रशासनिक और बौद्धिक क्षमता के बल पर देश की विदेश नीति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जब वैश्विक मंचों पर भारत का रुख तय करने की बात आती है, तो जयशंकर जैसे योग्य नेताओं की नीतिगत बातें 2 मिनट के क्लिप में सिमट जाती हैं। वहीं दूसरी ओर, चुनाव हारे हुए नेता जब विदेश नीति पर कोई बचकाना बयान देते हैं, तो मीडिया उस पर 2 घंटे का प्राइम टाइम डिबेट चलाता है। योग्यता को दरकिनार कर सनसनी को तरजीह दी जाती है।

तमिलनाडु की राजनीति में के. अन्नामलाई एक ऐसा नाम हैं, जो बिना किसी राजनीतिक विरासत के आगे आए। वे एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने आईआईएम से पढ़ाई की और बाद में अपनी प्रशासनिक नौकरी छोड़कर जमीन पर राजनीति शुरू की। मीडिया अक्सर ऐसे नेताओं के विजन, उनकी प्रशासनिक सोच या उनके द्वारा उठाए गए बुनियादी मुद्दों पर गहराई से रिपोर्टिंग नहीं करता। इसके बजाय, अगर कोई वंशवादी नेता अन्नामलाई पर कोई निजी टिप्पणी कर दे, तो मीडिया उस विवाद को 24 घंटे चलाएगा, लेकिन अन्नामलाई की शैक्षणिक या प्रशासनिक पृष्ठभूमि से निकले विचारों पर कोई बहस नहीं होगी। इसी प्रकार पूर्वोत्तर भारत में सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्वा शर्मा जैसे नेताओं ने बिना किसी बड़े राजनीतिक घराने के ठप्पे के, छात्र राजनीति और जमीनी संघर्षों से अपनी पहचान बनाई। मीडिया को पूर्वोत्तर के इन नेताओं के विकास मॉडल या उनकी योग्यता से ज्यादा दिलचस्पी इस बात में रहती है कि वे किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ क्या तीखा बयान दे रहे हैं। मीडिया उनकी योग्यता को तब तक तवज्जो नहीं देता, जब तक वे टीवी की टीआरपी के हिसाब से मसालेदार बयान न दें।

जो नेता अपनी नीतियों और नफरत भरी राजनीति के कारण जनता द्वारा पूरी तरह ठुकरा दिए गए हैं, उनके लिए सोशल मीडिया एक संजीवनी बूटी बन चुका है। सोशल मीडिया पर हर नेता ने अपनी एक ट्रोल आर्मी और समर्थकों का एक छोटा समूह बना लिया है। यहां वे खुद को पीड़ित और देश का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करते हैं। पहले नेता को अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए काम करना पड़ता था। आज एक ट्वीट या फेसबुक लाइव करके कोई भी पूर्व-नेता खुद को ज्ञान का भंडार घोषित कर देता है। टीवी चैनल अब खुद से खबरें ढूंढने के बजाय नेताओं के इन्हीं ट्वीट्स और रील्स पर ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं। यानी जनता द्वारा खारिज नेता ही अब मीडिया का कंटेंट तय कर रहे हैं। जब मीडिया और सोशल मीडिया का केंद्र बिंदु योग्यता के बजाय सनसनी और खारिज किए गए नेताओं का आलाप बन जाता है, तो इसके गंभीर परिणाम पूरे देश को भुगतने पड़ते हैं।

स्वास्थ्य, बेरोजगारी, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर से जनता का ध्यान भटक जाता है। देश का युवा यह देखता है कि योग्यता, पढ़ाई और जमीनी काम करने वालों की जगह टीवी पर बहस करने और नफरत फैलाने वाले ही दिख रहे हैं, जिससे राजनीति का स्तर गिरता है। जब मीडिया सवाल पूछना बंद कर देता है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनता के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। कुल मिलाकर, आज का मीडिया और वायरल संस्कृति भले ही जनता के ठुकराए गए नेताओं को मसीहा बनाकर पेश कर रही हो, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक लोकतंत्र के हित में नहीं है। टीवी स्टूडियोज में योग्य, पढ़े-लिखे और जमीनी संघर्ष से आए नेताओं (चाहे वे किसी भी दल के हों) को जगह देनी होगी। खारिज किए गए नेताओं की लंबी बाइट्स दिखाने के बजाय उनसे कड़े और तथ्यात्मक सवाल पूछने का साहस दिखाना होगा। जब तक मीडिया टीआरपी की हवस छोड़कर योग्यता को तरजीह नहीं देगा और जनता के असली मुद्दों पर सवाल नहीं पूछेगा, तब तक सोशल मीडिया के ये स्वघोषित ज्ञानी और ठुकराए गए नेता देश के विकास की दौड़ में अड़ंगा लगाते रहेंगे। लोकतंत्र की असली मजबूती शोर में नहीं, बल्कि सही सवाल में छिपी है।

अनशन

अरुण कुमार डनायक

लेखक समाजसेवी हैं।

सोनम वांगचुक और शिक्षा सुधार का एजेंडा

भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल सरकार पर निर्भर नहीं हो सकता; इसके लिए नवाचार, जवाबदेही और उद्यमशीलता को जोड़ना होगा। देश की सबसे बड़ी पूँजी उसकी युवा जनसंख्या है, जो तभी लाभकारी बनेगी जब उसे गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख शिक्षा मिले। शिक्षा की गुणवत्ता विद्यालय के सरकारी या निजी होने से नहीं, बल्कि योग्य शिक्षकों, प्रभावी प्रबंधन और जवाबदेही से तय होती है। भवन, स्मार्ट क्लास या डिजिटल उपकरण पर्याप्त नहीं हैं; असली सुधार अच्छे शिक्षण, नियमित मूल्यांकन और शिक्षकों की जिम्मेदारी से आता है। विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार आवश्यक है, ताकि यह अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बने। अत्यधिक नियम-कानून नए शिक्षा उद्यमियों के प्रवेश में बाधा डालते हैं; इन्हें सरल और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। आज की अर्थव्यवस्था में शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री नहीं, बल्कि कौशल और रोजगार योग्य प्रतिभा का विकास है।

जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक ने 24 जून को गुरुग्राम में केंद्र सरकार के दो मंत्रियों जे.पी. नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह से लिखित आश्वासन मिलने के बाद 26 दिन लंबा अनशन समाप्त किया। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला और लंबे समय से जारी छात्र आंदोलन ने निर्णायक मोड़ लिया। सरकार ने वादा किया कि जंतर-मंतर और संसद मार्च में शामिल छात्रों पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा तथा नीट प्रश्नपत्र लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने पर विचार किया जाएगा। साथ ही संसद में शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के कदम उठाने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो इंस्टाग्राम वीडियो संदेशों में फास्ट-ट्रैक अदालतों और कठोर दंड वाले विधेयक का प्रारूप तैयार होने की बात कही, हालांकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन लगातार बैठकों और बढ़ते युवा प्रतिरोध के दबाव में अंततः 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया।

महात्मा गांधी के दृष्टिकोण में उपवास केवल राजनीतिक दबाव का साधन नहीं था, बल्कि आत्मशुद्धि, नैतिक जागरण और संवाद की प्रेरणा भी था। उन्होंने अपने आंदोलनों में कभी संवाद और समझौते के द्वार बंद नहीं किए; सप्रू और जयकर जैसे मध्यस्थों ने कई अवसरों पर समाधान का मार्ग प्रशस्त किया। इसी परंपरा में सोनम वांगचुक के अनशन और छात्र आंदोलन की समाप्ति को किसी पक्ष की हार-जीत नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक सहमति और जवाबदेही की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जाना चाहिए।

जंतर-मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन तेजी से कई राज्यों में फैल गया और उनकी मांगें नीट प्रश्नपत्र लीक से आगे बढ़कर पूरी शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही तक पहुँच गईं। छात्रों का कहना है कि केवल नए कानून पर्याप्त नहीं होंगे; संस्थागत कमजोरियों और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर गंभीर ध्यान देना होगा। बार-बार होने वाले प्रश्नपत्र लीक ने उनकी मेहनत और भविष्य को असुरक्षित बना दिया है, जबकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए छात्र सरकारी और निजी विद्यालयों के बीच बढ़ती असमानता पर चिंतित हैं। पुलिस बल प्रयोग से घायल होने के बावजूद छात्रों ने आंदोलन जारी रखा, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल एक परीक्षा का न्याय नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार है। छात्रों ने सीबीएसई मूल्यांकन प्रणाली, सीयूईटी में देरी, परीक्षा केंद्रों की अव्यवस्था, शिकायत निवारण तंत्र की कमजोरियों को भी गंभीर समस्याएँ बताया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण माध्यम चुनाव, संसदीय उत्तरदायित्व और आवश्यकता पड़ने पर मंत्रीस्तरीय दायित्व तय करना भी है। सरकार ने अंततः शिक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर एक कदम उठाया, हालांकि इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी का स्पष्ट स्वीकार नहीं दिखता। उच्च शिक्षा विभाग में सचिव स्तर पर फेरबदल और एनटीए के संविदा कर्मियों को हटाना छात्र संगठनों के अनुसार उनकी मूल मांगों का समाधान नहीं है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के संदेश को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने संसद के भीतर और बाहर शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक चर्चा का दबाव बनाया। इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि विपक्ष की सरकार को चौतरफा घेरने की रणनीति सफल रही। अब जब छात्र अपने घर लौट चुके हैं, संसद के सुचारू रूप से चलने और शिक्षा सुधार जैसे दीर्घकालिक विषयों पर राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति बनने की संभावना है। फिल्म जगत, साहित्यकारों, शिक्षाविदों, वकीलों, मानवाधिकार संगठनों और नागरिक समाज के व्यापक समर्थन ने इस आंदोलन को छात्रों के दायरे से निकालकर शिक्षा सुधार और लोकतांत्रिक जवाबदेही का व्यापक सामाजिक अभियान बना दिया।

भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल सरकार पर निर्भर नहीं हो सकता; इसके लिए नवाचार, जवाबदेही और उद्यमशीलता को जोड़ना होगा। देश की सबसे बड़ी पूँजी उसकी युवा जनसंख्या है, जो तभी लाभकारी बनेगी जब उसे गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख शिक्षा मिले। शिक्षा की गुणवत्ता विद्यालय के सरकारी या निजी होने से नहीं, बल्कि योग्य शिक्षकों, प्रभावी प्रबंधन और जवाबदेही से तय होती है। भवन, स्मार्ट क्लास या डिजिटल उपकरण पर्याप्त नहीं हैं; असली सुधार अच्छे शिक्षण, नियमित मूल्यांकन और शिक्षकों की जिम्मेदारी से आता है। विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार आवश्यक है, ताकि यह अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बने। अत्यधिक नियम-कानून नए शिक्षा उद्यमियों के प्रवेश में बाधा डालते हैं; इन्हें सरल और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। आज की अर्थव्यवस्था में शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री नहीं, बल्कि कौशल और रोजगार योग्य प्रतिभा का विकास है।

परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं का विस्तार, प्रश्नपत्रों की डिजिटल सुरक्षा, बायोमेट्रिक सत्यापन और एआई निगरानी अपनाई जानी चाहिए। मूल्यांकन में स्वचालित ग्रेडिंग से परिणाम शीघ्र और निष्पक्ष होंगे। साथ ही, परीक्षा नियामक संस्थाओं को स्वतंत्र और जवाबदेह बनाया जाए। एनटीए की संस्थागत क्षमता, तकनीकी दक्षता और स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना भी आवश्यक है, ताकि उच्च स्तरीय परीक्षाओं का संचालन विश्वसनीय ढंग से हो सके। बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं की ऑनलाइन प्रणाली इसकी सफलता का प्रमाण है। केवल परीक्षा प्रणाली में सुधार पर्याप्त नहीं है। जब लाखों विद्यार्थी सीमित सीटों के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा में रहेंगे, तो प्रश्नपत्र लीक और अनियमितताओं का असर गंभीर बना रहेगा। इसलिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों और सीटों की संख्या बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है।

शिक्षा व्यवस्था को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा कि किसी विद्यार्थी का भविष्य केवल एक परीक्षा पर निर्भर न रहे। इसके लिए बहु-स्तरीय मूल्यांकन, अनेक अवसर और सतत आकलन जैसी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। भारत में प्रश्नपत्र लीक की समस्या नई नहीं है। पिछले दशक में भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में कई राज्यों तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी घटनाएँ बार-बार हुई हैं।

यह किसी एक परीक्षा या संस्था की विफलता नहीं, बल्कि परीक्षा प्रशासन की संरचनात्मक कमजोरी को दर्शाता है। नीट प्रश्नपत्र लीक से शुरू हुआ यह आंदोलन अब शिक्षा सुधार के व्यापक राष्ट्रीय विमर्श का रूप ले चुका है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे उस उत्पन्न दबाव का प्रत्यक्ष परिणाम यदि केवल दोषियों को दंड दिलाने तक सीमित रहता है, तो इसका प्रभाव अल्पकालिक होगा। किंतु यदि इसके परिणामस्वरूप भारत की परीक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से सुरक्षित, जवाबदेह और छात्र-केंद्रित बनती है, तो यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन की ऐतिहासिक शुरुआत सिद्ध हो सकती है। आने वाले दिनों में सरकार द्वारा प्रस्तावित कानूनी और संस्थागत सुधार तथा संसद में होने वाली चर्चा यह तय करेगी कि यह आंदोलन केवल तत्काल संकट तक सीमित रहता है या दीर्घकालिक परिवर्तन का आधार बनता है। और यदि यह नीति छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों व शैक्षिक संगठनों के साथ व्यापक विमर्श से बने, न कि केवल विषय विशेषज्ञों के सुझावों तक सीमित रहे, तो यह सुधार और भी सार्थक होगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

दृष्टिकोण

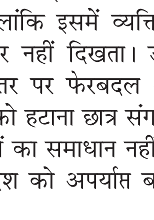

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं।

क्या लौट रही है अहिंसा की भाषा?

हाल के वर्षों में भारत में कुछ युवा समूहों ने अहिंसक प्रतिरोध, नागरिक भागीदारी, जलवायु न्याय, पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर नए ढंग से सक्रियता दिखाई है। इसे कुछ लोग गांधीवादी मूल्यों की नई अभिव्यक्ति मानते हैं, जबकि अन्य कुछ लोग इसे सीमित प्रभाव वाला शहरी आंदोलन मानते हैं।

एक समय था जब भारत की सार्वजनिक चेतना में महात्मा गांधी केवल इतिहास का अध्याय नहीं, बल्कि व्यवहार का मानदंड थे। सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन, संयम और नैतिक साहस जैसे मूल्य सामाजिक जीवन और राजनीति की भाषा का हिस्सा थे। समय के साथ परिस्थितियाँ बदलीं। उपभोक्तावाद, तीव्र प्रतिस्पर्धा, सोशल मीडिया की तात्कालिकता और राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच गांधी का नाम तो बना रहा, पर उनके विचारों की ज़मीन धीरे-धीरे सिकुड़ती चली गई। आज गांधी की तस्वीर मुद्रा पर दिखाई देती है, किंतु उनके विचार सार्वजनिक जीवन में पहले जैसी केंद्रीय उपस्थिति उस तरह रखते हैं या नहीं, यह अवश्य विचारणीय विषय है।

इसी बीच एक दिलचस्प परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जिस जेन-जी (जनरेशन जेड) को अक्सर मोबाइल, रील, गेमिंग और त्वरित संतुष्टि की पीढ़ी कहकर खारिज कर दिया जाता है, उसी पीढ़ी का एक हिस्सा सामाजिक आंदोलनों में नई संवेदनशीलता के साथ सामने आ रहा है। यह आंदोलन पारंपरिक गांधीवाद की हूबहू पुनरावृत्ति नहीं है, लेकिन उसके भीतर गांधी के कई मूल तत्वों की प्रतिध्वनि अवश्य सुनाई देती है।

देश के अनेक विश्वविद्यालयों, पर्यावरण अभियानों, महिला अधिकार, लैंगिक समानता, शिक्षा, पारदर्शिता और स्थानीय समुदायों के प्रश्नों पर युवा समूहों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन, जनसंवाद, पदयात्राएँ, डिजिटल हस्ताक्षर अभियान और रचनात्मक विरोध के नए तरीके अपनाए हैं। इनमें हिंसा की अपेक्षा संवाद, दमन की अपेक्षा नैतिक दबाव और नफरत की अपेक्षा सहभागिता पर अधिक बल दिखाई देता है। यही वह बिंदु है जहाँ गांधी की विरासत अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लगती है।

हालाँकि यह निष्कर्ष निकाल लेना जल्दबाज़ी होगी कि भारत में गांधीवाद पहले की तरह पूरी शक्ति से लौट आया है। जेन-जी स्वयं अनेक विरोधाभासों से घिरी हुई पीढ़ी है। एक ओर वह सामाजिक न्याय और पर्यावरण की बात करती है, तो दूसरी ओर वही पीढ़ी डिजिटल ट्रोलिंग, त्वरित आक्रोश, उपभोक्तावादी जीवनशैली और सूचना के सतही उपभोग का भी हिस्सा है। गांधी जिस आत्मानुशासन, त्याग और सादगी की बात करते थे, वह अभी भी व्यापक युवा संस्कृति का प्रमुख गुण नहीं बन पाया है। दरअसल आज का युवा गांधी को चरखे या खादी तक सीमित नहीं देखता। वह उन्हें सत्ता से प्रश्न पूछने के साहस, अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिरोध और नागरिक जिम्मेदारी के प्रतीक के रूप में पढ़ना चाहता है। यह गांधी की नई व्याख्या है। इस व्याख्या में सोशल मीडिया भी विरोध का मंच हो गया है, ऑनलाइन अभियान भी सत्याग्रह का एक आधुनिक रूप बन सकता है और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए सामुदायिक भागीदारी भी रचनात्मक कार्यक्रम का विस्तार मानी जा सकती है। यह भी ध्यान रखना होगा कि केवल आंदोलनों से गांधी का पुनर्जागरण संभव नहीं होगा। गांधी का सबसे बड़ा आग्रह आत्मपरिवर्तन था। यदि आंदोलन केवल विरोध तक सीमित रहें और जीवनशैली में ईमानदारी, पारदर्शिता, सहिष्णुता और आत्मसंयम न आए, तो गांधी केवल प्रतीक बनकर रह जाएंगे। दूसरी ओर यदि युवा अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों भूमिकाओं में इन मूल्यों को अपनाते हैं, तो गांधी की विचार-भूमि वास्तव में फिर से हरी हो सकती है।भारतीय समाज के लिए यह अवसर भी है और चुनौती भी। शिक्षा व्यवस्था, विश्वविद्यालय, नागरिक संगठन और मीडिया यदि युवाओं को केवल इतिहास का गांधी नहीं, बल्कि समकालीन संदर्भों का गांधी समझाने का प्रयास करें, तो लोकतंत्र को नई ऊर्जा मिल सकती है। जलवायु संकट, असमानता, डिजिटल घृणा और सामाजिक विभाजन जैसे प्रश्न आज उसी नैतिक नेतृत्व की मांग करते हैं जिसकी ओर गांधी ने संकेत किया था।

यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि जेन-जी ने गांधी को पुनर्जीवित कर दिया है। लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि गांधी पूरी तरह कभी अप्रासंगिक हो चुके हों। शायद अभी हम एक ऐसे संक्रमणकाल में हैं जहाँ गांधी की सूखी प्रतीत होने वाली विचार-भूमि पर कुछ नए अंकुर फूटते दिखाई दे रहे हैं। इन अंकुरों को पहचानने, पोषित करने और उन्हें स्थायी वृक्ष बनने का अवसर देने की आवश्यकता है।

संभव है कि भविष्य का गांधीवाद चरखे से नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकता, डिजिटल नैतिकता, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और अहिंसक लोकतांत्रिक सहभागिता के रूप में हमारे सामने आए। यदि ऐसा हुआ, तो यह केवल गांधी की वापसी नहीं होगी, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए भी एक आश्वस्तकारी संकेत होगा।

मुद्दा

जयदेव राठी

लेखक एडवोकेट हैं।

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा- ना तेरी जीत, ना मेरी हार

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि यह उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा कि वह नहीं चाहते कि देश के युवाओं को भ्रम और राजनीतिक टकराव के जाल में फंसाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने अपने पत्र में यह चिंता भी व्यक्त की कि राष्ट्रविरोधी ताकतें इस स्थिति का लाभ उठा सकती हैं और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकती हैं। यहीं से यह मुद्दा केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं रह जाता। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब किसी आंदोलन का आकार राष्ट्रीय स्तर पर फैल जाता है, तब सुरक्षा एजेंसियां भी उससे जुड़े संभावित खतरों का आकलन करती हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि सरकार को आंदोलन के स्वरूप को लेकर गंभीर सुरक्षा संबंधी चिंताओं से अवगत कराया गया था।

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां फैसले केवल सत्ता बचाने के लिए नहीं, बल्कि समय की मांग और राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर भी लिए जाते हैं। राजनीति में अक्सर किसी फैसले को हार और जीत के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें किसी व्यक्ति, दल या आंदोलन की जीत अथवा हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ऐसा ही एक फैसला प्रतीत होता है। यह केवल एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति का उदाहरण है जिसमें परिस्थितियों को देखते हुए बड़े निर्णय लिए जाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन्हें व्यापक जनभावनाओं और परिस्थितियों को देखते हुए वापस लिया गया या उनमें बदलाव किया गया। चाहे कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय हो अथवा अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव, सरकार ने कई बार यह संदेश दिया है कि लोकतंत्र में संवाद और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना कमजोरी नहीं, बल्कि राजनीतिक परिपक्वता का परिचायक है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब देशभर में छात्र आंदोलनों ने व्यापक स्वरूप ले लिया था। नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों ने युवाओं के बीच असंतोष पैदा किया। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे ने स्वाभाविक रूप से जनभावनाओं को प्रभावित किया।

आंदोलन का मूल मुद्दा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही था, जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक और उचित मांग कही जा सकती है। लेकिन भारत सहित दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक देशों का इतिहास बताता है कि बड़े जन आंदोलनों में समय के साथ कई ऐसे तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं जिनका मूल मुद्दे से सीधा संबंध नहीं होता। आंदोलनों की भीड़ में ऐसे समूह शामिल हो जाते हैं जो अपनी वैचारिक, राजनीतिक अथवा अराजक एजेंडों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए केवल आंदोलन की मांगों को देखना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उससे उत्पन्न होने वाली व्यापक परिस्थितियों का भी आकलन करना पड़ता है। देशभर में चल रहे छात्र आंदोलन ने धीरे-धीरे राजनीतिक स्वरूप भी ग्रहण कर लिया था। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की जवाबदेही का मुद्दा बनाया, वहीं कई सामाजिक और राजनीतिक समूह भी इससे जुड़ते चले गए। राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर विभिन्न राज्यों तक इसका प्रभाव दिखाई देने लगा था। संसद के मानसून सत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही थी।

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि यह उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा कि वह नहीं चाहते कि देश के युवाओं को भ्रम और राजनीतिक टकराव के जाल में फंसाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने अपने पत्र में यह चिंता भी व्यक्त की कि राष्ट्रविरोधी ताकतें इस स्थिति का लाभ उठा सकती हैं और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकती हैं। यहीं से यह मुद्दा केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं रह जाता। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब किसी आंदोलन का आकार राष्ट्रीय स्तर पर फैल जाता है, तब सुरक्षा एजेंसियां भी उससे जुड़े संभावित खतरों का आकलन करती हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि सरकार को आंदोलन के स्वरूप को लेकर गंभीर सुरक्षा संबंधी चिंताओं से अवगत कराया गया था। हालांकि इन रिपोर्टों में विस्तृत आधिकारिक

खुफिया इनपुट सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, इसलिए उन्हें अंतिम सत्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन यह निश्चित है कि सरकार ने आंदोलन के बढ़ते स्वरूप और संभावित परिणामों को ध्यान में रखकर राजनीतिक निर्णय लिया।

लोकतंत्र में कभी-कभी सरकारें यह तय करती हैं कि किसी व्यक्ति का पद बचाने से अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक शांति और राष्ट्रीय हित है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी संभवतः इसी श्रेणी का निर्णय है। यदि एक मंत्री के पद छोड़ने से देशभर में तनाव कम होता है, छात्रों का भविष्य सुरक्षित होता है और व्यापक राजनीतिक टकराव टलता है, तो इसे केवल राजनीतिक पराजय कहना उचित नहीं होगा।

यह भी समझना आवश्यक है कि किसी मंत्री का इस्तीफा यह सिद्ध नहीं करता कि वह व्यक्तिगत रूप से दोषी है। संसदीय लोकतंत्र में नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी का सिद्धांत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार मंत्री प्रशासनिक अथवा राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पद छोड़ते हैं ताकि संस्थाओं की विश्वसनीयता बनी रहे और व्यवस्था आगे बढ़ सके। वर्तमान घटनाक्रम ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है। क्या केवल मंत्री के इस्तीफे से देश की शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से 'नहीं' है। यदि परीक्षा प्रणाली में संरचनात्मक खामियां हैं तो उनका समाधान संस्थागत सुधारों से ही संभव होगा। परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित बनाना, पेपर लीक के मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई करना, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना और छात्रों का विश्वास बहाल करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। आंदोलन समाप्त हो जाना किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। असली चुनौती उसके मूल कारणों को समाप्त करना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि छात्र संगठन, सरकार और समाज तीनों मिलकर शिक्षा सुधारों को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाएं। युवाओं की ऊर्जा को राजनीतिक टकराव का माध्यम बनाने के बजाय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगाया जाना चाहिए।

भारतीय लोकतंत्र की ताकत यही है कि यहां सरकारें झुकती भी हैं और संवाद भी करती हैं। एक मंत्री का इस्तीफा किसी आंदोलन की अंतिम जीत नहीं है और न ही सरकार की हार। यदि इस निर्णय से देश में शांति बनी रहती है, छात्रों का भविष्य सुरक्षित होता है और शिक्षा सुधारों का मार्ग प्रशस्त होता है, तो यह लोकतंत्र की परिपक्वता का परिचायक माना जाना चाहिए।

अंततः, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को हार और जीत के राजनीतिक तराजू पर तौलने के बजाय राष्ट्रहित के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत किसी दल, नेता या आंदोलन की नहीं होती, बल्कि उस व्यवस्था की होती है जो समय आने पर स्वयं को सुधारने का साहस रखती है। इसलिए शायद इस पूरे घटनाक्रम को एक ही पंक्ति सबसे बेहतर ढंग से व्यक्त करती है-ना तेरी जीत, ना मेरी हार; सबसे ऊपर राष्ट्र का सम्मान और देशहित का विचार।

सामयिक

मुकेश जोशी

लेखक राजनीतिक विचारक तथा प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन के निदेशक हैं।

कॉकरोच आंदोलन देश के इतिहास का सबसे अश्लील आंदोलन

पेपर लीक के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन जब पूरी तरह अनियंत्रित और अराजक हो चला था तब धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अश्लील और बेकाबू हो रहे लड़के-लड़कियों का आंदोलन वहीं ठप करवाते हुए जंतर मंतर खाली करवा लिया। काबू से बाहर होकर अराजक पहले किसान आंदोलन भी हुआ था लेकिन वो कभी इतना गंदा और अश्लील नहीं हुआ था।

जैसा कि नाम से ही जाहिर है इस आंदोलन के पीछे सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी थी। सब जानते हैं कॉकरोच कितना घिनोना और गंदा प्राणी है जो गंदगी से ही पैदा होता है और गंदगी में ही रहता है तो ऐसे गंदे नाम वाली पार्टी से आप स्वच्छता और शिष्टता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इस काकरोची आंदोलन से पहले देश ने आजादी का आंदोलन, दूसरी आजादी यानी आपातकाल के खिलाफ आंदोलन, अन्ना आंदोलन जिससे केजरीवाल जैसे कॉकरोच पैदा हो गए, किसान आंदोलन, शाहीन बाग जैसे बड़े-बड़े आंदोलन हुए लेकिन किसी भी आंदोलन में इतनी भयंकर किस्म की अश्लीलता कभी नहीं घुसने पाई। यहां तक कि शाहीन बाग जैसा एक वर्ग विशेष का आंदोलन भी तमाम विसंगतियों के बावजूद अश्लीलता का शिकार नहीं हुआ। आजादी के जेएनयू छाप नारे जोर शोर से लगते रहे किन्तु बात कभी बिलो द बेल्ट नहीं की गई। प्राय: सारे आंदोलन मर्यादित ही रहे। लाठीचार्ज केन चार्ज, वाटर चार्ज, अश्रु गैस ही नहीं कई बार गोलियां भी चलानी पड़ीं लेकिन तब भी इन आंदोलनों में गालियाँ नहीं घुसी। जबकि 20 जुलाई से शुरू हुए इस काकरोची आंदोलन जिसे कथित तौर पर जेन जी का प्रचारित किया जा रहा है पहले दिन से ही गाली-गलौच से भरा दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन को अश्लील आंदोलन इसलिए लिखा गया है कि सुबह से रात तक छात्राएं अपने प्रदर्शन में न सिर्फ अश्लील नारेबाजी करती देखी जा रही हैं वरन उनकी तख्तियों पर भी अश्लील व्यंग्य चित्र मीम्स नजर आ रहे थे। गालियां तो वैसे ही गन्दी और अश्लील होती हैं लेकिन इस गंदगी को ये छात्राएं गंदगी और अश्लीलता के निम्नतम स्तर पर ले जा चुकी थी। दृश्य मीडिया में ये गालियां खूब जमकर प्रचारित हो रही हैं किन्तु प्रिंट मीडिया में ये अशोभनीय गालियाँ न तो लिखी जा सकती हैं न प्रकाशित की जा सकती हैं।

सोनम वांगचुक आए भूख हड़ताल धरने पर बैठे। कोर्ट के दखल से वहां से उठा भी लिए गए और अब प्रधानमंत्री मोदी के कुछ फैसलों के बाद उन्होंने अनशन तोड़ भी दिया। वांगचुक की समझदारी और दूरदर्शिता की तारीफ करना होगी। वरना तो यहां तक कहा जा रहा था कि अराजक तत्वों के हाथों कमजोर हो चुके वांगचुक को मंच पर ही निबटाया जाकर देश भर में सरकार विरोधी माहौल बनाकर हिंसा फैला दी जाए। इस तरह तख्ता पलट करने और सत्ता हथियाने के विदेशी और विपक्षी मंसूबों पर गृह मंत्रालय तथा सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया। अब भी वांगचुक तो जैसे अपनी मांगें रखकर अलग हो चुके हैं, नीट परीक्षा तो एक तरफ धरी रह गई लेकिन आंदोलन अब विशुद्ध अराजक तत्वों ने हथिया लिया। जंतर मंतर से गालियों और अश्लीलता से भरी हजारों रीलें सोशल मीडिया पर वायरल की गईं।

दु:ख और आश्चर्य की बात यह है कि ये वीभत्स गालियाँ लड़कों द्वारा नहीं लड़कियों द्वारा दी जा रही थीं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके भले ही कह रहे हों कि हमारा आंदोलन अहिंसक और शांतिपूर्ण है लेकिन जंतर मंतर से आ रहे सैकड़ों वीडियो बता रहे हैं कि आंदोलन कतई शांतिपूर्ण नहीं रहा है। सैकड़ों पुलिसकर्मी पिटे ही नहीं, बुरी तरह जख्मी हुए थे।

हमारे यहां पुरुष समाज तो सदियों से गाली देता आया है। लेकिन शर्मनाक यह है कि हमारी लड़कियां खुलेआम गालियां ही नहीं दे रही हैं, बुजुर्ग प्रधानमंत्री के विरोध में अश्लीलतम नारेबाजी कर सार्वजनिक उपहास उड़ा रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी बेहद सहिष्णु हैं। उन्होंने अपने सार्वजनिक अपमान का हिसाब अपनी तरह चुकाया ही दिया है लेकिन बगैर कुछ बोले। ये गालीबाज लड़कियां खुद सोचें कि उनके पास ये गाली संस्कार कहां से आए? यदि गाली देना आ भी गई तो उन्हें सार्वजनिक रूप से समूह में प्रदर्शित करने का साहस कहां से आया? ये सीजेपी की भीड़ असल में आम आदमी पार्टी के असामाजिक तत्वों की भाड़े की भीड़ थी जो तोड़फोड़ कर आंदोलन को हिंसक रूप दे रही थी। इस भीड़ के पीछे खड़े कुछ राजनीतिबाज अपने उद्देश्य में इसलिए कुछ हद तक सफल हुए हैं लेकिन इनका उद्देश्य नीट या विद्यार्थियों का हित कतई नहीं है। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को गालीबाज, अश्लील, जाहिल बनाकर व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा करना ही है। इस समूचे आंदोलन के पीछे सरकार की संवादहीनता और लापरवाही जिम्मेदार है। यदि सरकार पहले ही दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती तो आंदोलन खड़ा ही नहीं होता और खड़ा भी हो जाता तो इतना विकराल रूप नहीं ले पाता। इस बीच आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस गए जिससे प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाने वालों को मौका मिल गया। गृहमंत्री अमित शाह की छवि एक सख्त प्रशासक की बनी हुई है पर ऐसे अराजक गाली-गलौच भरे आंदोलन उनकी इस इमेज पर बट्टा लगाते हैं क्योंकि देश में इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री को इस कदर गालियां नहीं मिली होंगी। ऐसे हिंसक अराजक और असामाजिक आंदोलन राजधानी में गृह मंत्री की नाक के नीचे फैल जाना हमारे लोकतंत्र की ताकत तो बताता है लेकिन साथ ही हमारी गुप्तचर सेवाओं और गृह मंत्रालय की कमजोरी भी।अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है उन सारी लड़कियों लड़कों जो प्रधानमंत्री के लिए घोर अश्लील प्रदर्शन कर रहे थे इनके चेहरे पूरे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं इन्हें पहचान कर इनके खिलाफ फौरन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसी जुबानी क्रूरता को लोकतांत्रिक क्रूरता से ही कुचला जाना चाहिए।

विचार

रमेश कुमार 'रिपु'

लेखक स्तंभकार हैं।

जंतर-मंतर से उठी आवाज़ क्या बदलेगी राजनीति?

जंतर-मंतर से उठी यह आवाज़ अब केवल एक मंत्री के इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं दिखाई देती। इसके साथ सरकार की जवाबदेही, निर्णयों की पारदर्शिता और विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज को लेकर भी बहस तेज हुई है। लोकतंत्र में असहमति को सुनना सरकार की जिम्मेदारी है और तथ्यों के आधार पर सवाल उठाना विपक्ष तथा नागरिकों का अधिकार। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह आंदोलन केवल एक क्षणिक राजनीतिक घटना साबित होता है या भारतीय राजनीति में जवाबदेही और जनदबाव के नए अध्याय की शुरुआत करता है।

भारतीय लोकतंत्र में छात्र आंदोलन केवल शैक्षणिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब युवा सड़कों पर उतरते हैं, तो उनकी आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुँचती है और कई बार राजनीति की दिशा भी बदल देती है। हालिया छात्र आंदोलन ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या सरकारें केवल अपने संसदीय बहुमत के भरोसे चल सकती हैं, या उन्हें जनता, विशेषकर युवाओं की नाराज़गी और सवालों का भी जवाब देना होगा।

जंतर-मंतर सहित विभिन्न स्थानों पर हुए छात्र आंदोलन और प्रदर्शनों ने राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। आंदोलनकारियों का दावा है कि यह पिछले कई वर्षों का सबसे व्यापक छात्र आंदोलन है। जंतर-मंतर सहित विभिन्न स्थानों पर हुए प्रदर्शनों और पुलिस की कार्रवाई ने इस मुद्दे को और अधिक चर्चा में ला दिया। आंदोलन के बावजूद छात्रों का पीछे न हटना यह संकेत देता है कि उनके भीतर अपने मुद्दों को लेकर गहरा असंतोष है। यदि किसी एक मंत्री के इस्तीफे की मांग देशव्यापी छात्र आंदोलन का केंद्र बन जाती है, तो यह केवल एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि सरकार और युवाओं के बीच विश्वास, संवाद और जवाबदेही का भी प्रश्न बन जाता है।

इतिहास बताता है कि जब युवा सड़क पर उतरते हैं, तो सरकारों के सामने केवल कानून-व्यवस्था की चुनौती नहीं होती, बल्कि विश्वास बहाल करने की चुनौती भी होती है। लोकतंत्र में लाठी से आंदोलन दबाए जा सकते हैं, लेकिन संवाद के बिना असंतोष समाप्त नहीं होता।÷

सवाल यह है कि क्या छात्र आंदोलन सरकारों को झुका सकते हैं? लोकतंत्र, जवाबदेही और बदलती राजनीति लोकतंत्र में सरकारें केवल चुनावों से नहीं, बल्कि जनता की निरंतर प्रतिक्रिया से भी संचालित होती हैं। जब छात्र, किसान, मजदूर या अन्य सामाजिक वर्ग किसी मुद्दे पर बड़े पैमाने पर आंदोलन करते हैं, तो उसका प्रभाव केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहता; वह संसद, सरकार और राजनीतिक दलों की रणनीति तक पहुँचता है।

जंतर मंतर सहित देश के अन्य राज्यों में हाल के छात्र आंदोलनों ने यह प्रश्न फिर खड़ा कर दिया है कि क्या आज का भारत भी उसी दौर में प्रवेश कर रहा है, जहाँ संगठित जनदबाव सरकारों को अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। यदि किसी केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग व्यापक राजनीतिक मुद्दा बनती है, तो यह केवल एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं रहता, बल्कि सरकार की जवाबदेही की परीक्षा बन जाता है।

दूसरा बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भविष्य में अन्य मंत्रियों के खिलाफ भी इसी तरह राजनीतिक और जनदबाव खड़ा हो सकता है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल उठाना है और सरकार का काम उनका उत्तर देना। यदि शिक्षा, रक्षा, गृह या परिवहन जैसे मंत्रालयों के निर्णयों पर जनता के एक हिस्से में असंतोष है, तो विपक्ष उन मुद्दों को राजनीतिक रूप से उठाएगा। लेकिन किसी मंत्री का इस्तीफा होगा या नहीं, यह केवल जनभावना से नहीं बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों, तथ्यों और सरकार के आकलन पर भी निर्भर करता है।मणिपुर हिंसा, राष्ट्रीय सुरक्षा, शहीदों से जुड़े प्रश्न या ईंधन नीति जैसे विषयों पर भी देश में अलग-अलग मत हैं। इन मुद्दों पर सरकार की आलोचना भी हुई है और सरकार ने अपने पक्ष में स्पष्टीकरण भी दिए हैं। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि इन विषयों पर खुली बहस हो और तथ्यों के आधार पर जवाबदेही तय हो। लेकिन हैरानी वाली बात है कि छात्रों की जंतर मंतर पर 36 दिनों की लगातार हड़ताल और बर्बर लाठी चार्ज के बाद सरकार जागी और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। सवाल यह है कि क्या सरकार अपनी जवाबदेही सिर्फ हड़ताल और आंदोलन से तय करती है।

इथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर भी बहस जारी है। सरकार इसे आयातित तेल पर निर्भरता कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और प्रदूषण घटाने की नीति के रूप में प्रस्तुत करती है। वहीं कुछ वाहन मालिकों और विशेषज्ञों ने कुछ वाहनों में तकनीकी समस्याओं की शिकायतें भी उठाई हैं। इसलिए इस विषय पर व्यापक तकनीकी अध्ययन और उपभोक्ताओं की शिकायतों का निष्पक्ष मूल्यांकन आवश्यक है। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि जब जनता का असंतोष व्यापक और संगठित रूप लेता है, तब सबसे मजबूत सरकारों को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हर आंदोलन सरकार को झुकाने में सफल नहीं होता। उसकी सफलता नेतृत्व, जनसमर्थन, मुद्दे की गंभीरता और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि सत्ता और जनता के बीच संवाद बना रहे। यदि सरकार जनता की आवाज़ सुनती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, और यदि जनता अपनी बात शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक तरीके से रखती है, तो वह लोकतंत्र की सबसे बड़ी संरक्षक बन जाती है।

लोकतंत्र में किसी सरकार की सबसे बड़ी ताकत उसका बहुमत नहीं, बल्कि जनता का विश्वास होता है। और जनता का विश्वास बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है,जवाबदेही, संवाद और पारदर्शिता। लोकतंत्र की असली शक्ति केवल संसद में जुटे बहुमत से नहीं, बल्कि जनता के दिलों में बसे विश्वास से जन्म लेती है। बहुमत सत्ता दिला सकता है, लेकिन जनता का विश्वास ही सत्ता को सम्मान और स्थायित्व देता है। जवाबदेही, संवाद और पारदर्शिता इन्हीं तीन स्तंभों पर लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति खड़ी होती है। हर लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह जनता के प्रति जवाबदेह रहे, संवाद बनाए रखे और अपने निर्णयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करे। जब विश्वास कमजोर पड़ता है, तब सबसे मजबूत बहुमत भी असहज होने लगता है। शहीद सैनिक किसी भी दल या सरकार के नहीं, पूरे राष्ट्र के होते हैं। यदि किसी सैन्य अभियान में शहादत हुई है, तो उनके प्रति सम्मान, पारदर्शिता और समय पर आधिकारिक जानकारी देना लोकतांत्रिक शासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि विपक्ष को लगता है कि इस जिम्मेदारी का निर्वहन पर्याप्त रूप से नहीं हुआ, तो उसका प्रश्न उठाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। वहीं सरकार पर भी यह दायित्व है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता के जानने के अधिकार के बीच संतुलन बनाते हुए यथासंभव स्पष्ट जानकारी दे।शहीदों की शहादत पर राजनीति हो सकती है, लेकिन उनकी शहादत का सम्मान राजनीति से ऊपर होना चाहिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना भी देशभक्ति है और शहीदों का सम्मान करना भी।संसद में रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान सैनिक शहीद हुए, तो यह स्वाभाविक है कि यह प्रश्न उठे कि इसकी सार्वजनिक जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। लोकतंत्र में शहीदों के प्रति सम्मान केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं होता, बल्कि उनके बलिदान के बारे में पारदर्शिता और जवाबदेही भी उसका हिस्सा है। यदि जनता और विपक्ष इस पर सवाल उठाते हैं, तो सरकार का दायित्व है कि वह स्पष्ट और तथ्यात्मक उत्तर दे।

रोने वाले रोना चाहें पर रो ना पाएं

व्यंग्य

डॉ. प्रेमचंद द्वितीय

लेखक व्यंग्यकार हैं।

जिस तरह से देश विदेश में लाफिंग क्लब में लोग हँस-हँसकर अपने मन को आल्हादित करते हैं, उसी तरह अब क्राइंग क्लब जैसी संस्थाओं में लोग रो-रो कर मन का बोझ हल्का करते हैं।

शहर की चौपाल पर जब ठहाके लगाकर और बुक्का फाड़ कर हँसने और मुस्कुराने की बात चली तो पं. शिवनारायण बोले कई लोग रो रो कर जिंदगी पूरी कर देते हैं। और कोई हँस-हँसकर जिंदगी को आनंद से भर देते हैं। वे बोले हाइटेक युग में जब रिश्ते सिमट गए हैं लोग एक दूसरे के साथ बैठने से कतराने लगे हैं और साथ बैठकर भी इमोशनली नहीं जुड़ते हैं तब बोझ से लदे भारी मन को हल्का करने के लिए रोना पड़ता है। वे बोले कई मर्तबा रोना मासूमियत का सबूत है और वहीं कई बार हँसना उपहास और हंसी उड़ाने का फेक्टर हो जाता है। वे बोले हंसी लोटपोट वाली होती है तो रोना सिसकी भर भर कर दिल के टुकड़े करने वाला होती है।

हँसने रोने की चर्चा को सुनकर सुनील भैया बोल पड़े कस्बे के मजरे, टोले, ओटले, चौपाल चौराहे, पटिए पर जब बातों में हंसी और रोने की बात आती है तो आनंद हमेशा हर बात को लेकर रोते रहते हैं, उनको रोतले स्वभाव से उन्हें, आनंद रोतला, के नाम से जानते हैं। और लोग कहते है आनंद के पास रोने का आनंद है, ठीक इसके विपरीत स्वामी मुस्कुरा-मुस्कुरा कर, स्वामी मुस्कुरा के, बन गए हैं तो कोई तो कोई दिल मिलाकर स्वामी, दिल मिला के तो कुछ हँस कर जश्न मना कर, स्वामी जश्न खिला के, नाम से पहचाने जाने लगे हैं। लेकिन मुस्कुराने की हकीकत को जांच तो पता चलेगा कि इसमें इमोशन का मिशन कहीं से कहीं नहीं होता है जबकि रोने में जो रो-रो कर भावनाओं को छलका कर मन का बोझ हल्का हो जाता है। वे बोले रो-रो कर कई राज लेते हैं तो कई फर्जी, आर्टिफिशियल रोना रोकर ऑफिस में लगी अर्जी को मंजूरी हासिल कर लेते हैं। कई रोने धोने के छोटे-छोटे आंसुओं से सहानुभूति का समंदर लूट लेते हैं।

इस पर पवन बाबू बोले दुनिया में हंसी उड़ाने वाले बहुत है। लोगों पर हँस-हँसकर और हंसा हंसा कर उन्होंने महसूस किया कि मानव शरीर के लिए रोने की और आंसुओं की जरूरत होती है ताकि आर्टिफिशियल हंसी हँस हँस कर जब हल्का न हो सके तो रो-रो कर हर कोई हल्का हो सकता है। जब आंसुओं की बात सामने आई तो अखिलेश जी बोले बगैर आंसुओं के रोने का कोई वजूद नहीं है। रोना कोई ट्रेंड, ट्रेड, फेशन नहीं है बल्कि मरी हुई भावनाओं को जीवित करने का लोशन है।

जब आंसूओं की बात शुरू हुई तो आशु जी बोले परेशानी को व्यक्त करने का हथियार आंसू होते हैं। आंसू कईयों के लिए कमजोरी हो सकती है लेकिन आंसुओं से लो और हाई प्रोफाइल का ड्रामा खेल सकते हैं।

इस पर शैलू जी बोले आंसू रिसर्च का विषय है। जब श्रीमती को प्याज काटते काटते आंख में आंसू आ जाते हैं तो वह आंसू इतने खतरनाक नहीं होते हैं जितने चुनाव के व्यक्त प्याज की कीमत के आंसू जब निकलते हैं तो प्याज सरकारों को रुला देते है और अक्सर प्याज चुनाव के दौरान रुलाने का काम करने में अभ्यस्त हो गए हैं। वे बोले आंसू घड़ियाली भी होते हैं और इन घड़ियाली आंसू से रोने वाले हंसी को रौंद देते हैं। जहां तक आंसू न हो, रोने का कोई महत्व नहीं है। मगर बगैर आंसुओं के लोग महंगाई का रोना रोते हैं आंसू पक्ष-विपक्ष को दोनों को रुला देते हैं। वैसे भी आंसू इमोशनल होते हैं लेकिन कई मर्तबा आंसू पत्थर बन जाते हैं जिनसे न तो रोया जाता है न हीं हंसा जाता है। गम और खुशी दोनों के आंसू अलग-अलग होते हैं। आंसू बेशकीमती होते हैं। ऊंट के आंसू बहुत महंगे बिकते हैं लेकिन मनुष्य के आंसू अमूल्य होते हैं। वे बोले जिस तरह मुस्कुराहट की आहट अच्छे-अच्छे काम बना देती है इस तरह रोने के आंसू अच्छों अच्छों को रुला कर अपना मतलब सिद्ध करा देते हैं। हाईटेक युग में लोग साथ में रोने वाले का साथ ढूंढते हैं। रोकर इमोशंस शेयर करते हैं और फिर हल्के होकर घर लौटते हैं। कुछ रो-रो कर अपनी यातना के किस्से कहानी बताते हैं। उम्र दराज और सीनियर सिटीजन साथ बैठकर केवल हंसी से नहीं वरन रो-रो कर अकेलेपन को दूर करते हैं।

वे बोले आज के जमाने में अकेलापन इतना है कि रोने वाले रोना चाहते है पर रो ना पाते है वस्तुत रोना मात्र इमोशन नहीं शरीर का एक सिस्टम है। कोई तो रोने में आठ-आठ आंसू रो देते हैं और फूट-फूट कर रोते हैं, कई अंधों के आगे भी रोते हैं कई आंसू पी-पी कर रोते हैं, खुशी और गम में भी रोते हैं लेकिन हर किसी के लिए रोना आसान नहीं है कि क्योंकि रोना भी एक आर्ट है! और रोने वाले रोना चाहे पर रो ना पाते हैं।

गौहर रजा का सरोज सम्मान से अभिनंदन

ग्वालियर। जनकवि मुकुट बिहारी सरोज के जन्मशताब्दी वर्ष में प्रसिद्ध कवि, लेखक,रचनाकार गौहर रज़ा को सरोज सम्मान 2026 से अभिनंदित किया गया। सम्मानित होने के बाद बोलते हुए गौहर रज़ा ने कहा कि मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा जब पिछली पीढ़ियों के ख्वाब बिखर रहे हैं। ऐसे मे सरोज जी जैसे पहले के और आज के साहित्यकारों ने रास्ता दिखाया है और यही कविता का काम है। उन्होंने कहा कि छोटी सी कविता और लेख भी हुकूमत के लिए खतरा बनता है और यह बात हुकूमत अच्छी तरह से जानती है। इस संदर्भ में उन्होंने नाजी जर्मनी के समय के कवि पास्टर निमोलर और फैज अहमद फैज की हम देखेंगे नज़्म का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यदि संघर्ष की राह पर चलना है तो अपने कलाकारों को याद करना बहुत जरूरी हैं। इसके लिए सरोज न्यास को उन्होंने बधाई दी।

प्रसिद्ध रचनाकार यश मालवीय की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में शुरुआत में जनकवि मुकुट बिहारी सरोज स्मृति न्यास की सचिव मान्यता सरोज ने बताया कि यह सम्मान मानवता,जनता और देश के हित के मुद्दे उठाकर, जो है उसे बेहतर बनाने की दिशा दिखाने वाले रचनाकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए दिया जाता है। अब तक इससे 23 कवियों, साहित्यकारों को अभिनंदित किया जा चुका है। सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। समारोह में ग्वालियर के वरिष्ठ गीतकार मोहन अम्बर जी के गीतों पर केन्द्रित डॉ. भगवान स्वरूप शर्मा चैतन्य द्वारा संपादित लोकमंगल के विशेषांक का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर उनके पुत्र शिवदान सिंह गहलोत, रविदान सिंह गहलोत भी उपस्थित थे।

जनसमस्याओं से जुड़े आवेदनों का गंभीरता से निराकरण किया जाए : कलेक्टर डॉ. सोनवणे

स्कूल फीस और पाठ्यपुस्तकों की विक्रय दरों में अनावश्यक बढ़ोतरी न हो, गड़बड़ी पर निगरानी कर कार्यवाही की जाए

● अवैध शराब और अवैध खनन पर सख्त कार्यवाही करने के कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने दिए निर्देश

छात्रावासों की व्यवस्थाओं का एसडीएम करें निरीक्षण

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आबकारी विभाग को विशेष रूप से चोपना और सालबर्डी क्षेत्र में लगातार सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध खनन के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करने को कहा।कलेक्टर ने कहा कि समय-सीमा के प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विभाग निर्धारित समय में जनहित और जनसमस्याओं से जुड़े प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को समय पर राहत मिल सके। बैठक में शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने निजी स्कूलों में अनावश्यक फीस वृद्धि और पाठ्य पुस्तकों सहित अन्य शैक्षणिक सामग्री के विक्रय पर सतत निगरानी रखने

के निर्देश दिए। सभी विद्यालयों में शौचालय, पेयजल और बिजली की समुचित व्यवस्था बनाए रखने तथा जनसहयोग से विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त बेंच उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने एमपीआरडीसी को प्रभातपट्टन के चारसी और सालबर्डी में खराब सड़कों की मरम्मत एवं रोड मार्किंग कराने के निर्देश दिए। सभी स्थानांतरित पटवारियों को तत्काल नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश देते हुए सख्त हिदायत दी कि ऐसा नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बाशिंदा, ग्वासेन और ढोंडरामहू सहित अन्य ग्रामों में विद्युत आपूर्ति सुधारने के निर्देश भी दिए। लोक सेवा गारंटी प्रकरणों की समीक्षा के दौरान समय-सीमा से बाहर आवेदन लंबित पाए जाने पर चोपना के नायब तहसीलदार पर अर्थदंड लगाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने एसडीएम, जनपद सीईओ और तहसीलदारों को छात्रावासों, आंगनवाड़ियों और स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने तथा मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता स्वयं परखने के निर्देश दिए। भीमपुर के ग्राम करिंदा में जलभराव की समस्या के शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने दुर्गम और नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए वायरलेस सिस्टम और एम्बुलेंस व्यवस्था सुदृढ़ करने को कहा। बैठक में बिना अनुमति अधिकारी-कर्मचारियों के अटैचमेंट पर सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर ने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय कार्यों में खानापूर्ति या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और ऐसे अधिकारियों के कार्य व्यवहार का उल्लेख सेवा पुस्तिका में किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत जामठी में जनजातीय भूमि पर दुकान निर्माण के मामले में सरपंच को नोटिस जारी करने तथा संबंधित सचिव के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित जनपद सीईओ को तीन दिन में सुधार सुनिश्चित करने और प्रगति नहीं होने पर वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। जनसुनवाई, संबल पंजीयन, अनुग्रह सहायता एवं अंत्येष्टि सहायता के लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के कार्यों, ग्रामों में क्लोरीनेशन तथा मानसून के दौरान जलजनित बीमारियों की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों को पेयजल गुणवत्ता बनाए रखने और जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए समन्वित प्रयास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के अंत में कलेक्टर ने आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए परेड, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने तथा पूर्वाभ्यास कराने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, संयुक्त कलेक्टर कामिनी ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

महावीर इंटरनेशनल द्वारा बैतूल में संभागीय अधिवेशन 'अनुभूति 2026' का आयोजन श्री जैन दादावाड़ी में

बैतूल। महावीर इंटरनेशनल के तत्वावधान मे संकल्प व सृजन के द्वारा बैतूल में संभागीय अधिवेशन 'अनुभूति 2026' का आयोजन श्री जैन दादावाड़ी में किया गया ।इस गरिमामय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वीर सोहनलाल जी वैद्य(अंतर्राष्ट्रीय सचिव) वीर प्रदीप जी टोंगिया (अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रीजन 7) वीर आयुष जैन (सेक्रेटरी रीजन 7) वीर पारसमल जी पारख (पूर्व अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष रीजन 7) वीर शांतिलाल जी पितलिया (पूर्व अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष) एवं कैप्टन सुमित सिंह जी के मुख्य आतिथ्य में समपन्न हुआ ।इसमें ग्वालियर , विदिशा , भोपाल एवं बैतूल केन्द्र के सदस्यों की उपस्थिति रही ।इस कार्यक्रम में विभिन्न सेवा एवं जन कल्याण के कार्य करने पर केन्द्रो एवं व्यक्तिगत पुरुस्कार प्रदान किए गये ।मीडिया प्रभारी वंदना पगारिया ने बताया कि लाइफ टाइम एचिवमेंट के लिए वीर पारस मल जी पारख (ग्वालियर) , वीर शांतिलाल जी पितलिया (विदिशा) एवं वीरा सरला जी तातेड़ (बैतूल) को सम्मानित किया गया इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ केन्द्र प्रथम बैतूल व्दितीय चंदना वीरा ग्वालियर , सर्वश्रेष्ठ चेयर पर्सन प्रथम वीरा अंशु पगारिया व्दितीय वीरा रुचि बोथरा , सर्वश्रेष्ठ सचिव वीरा करुणा गर्ग व्दितीय वीर अवनेश

जैन , सर्वाधिक उपस्थिति में चंदनावीरा ग्वालियर , बेबी किट वितरण प्रथम संकल्प बैतूल व्दितीय M I ग्वालियर , गरिमा प्रोजेक्ट प्रथम संकल्प बैतूल द्वितीय MI ग्वालियर , स्वास्थ्य जागरुकता प्रथम विदिशा केन्द्र व्दितीय संकल्प बैतूल , महिला सशक्तिकरण में संकल्प बैतूल , शिक्षा एवं कौशल वृद्धि प्रथम संकल्प बैतूल व्दितीय विदिशा केन्द्र एवं चंदन वीरा ग्वालियर ,खुशियों का बाजार प्रथम MI ग्वालियर द्वितीय चंदना वीरा ग्वालियर , विशिष्ट सेवा प्रथम संकल्प बैतूल व्दितीय MI ग्वालियर , महिला एवं बाल विकास प्रथम संकल्प बैतूल व्दितीय विदिशा केन्द्र , पर्यावरण प्रथम संकल्प बैतूल व्दितीय चंदनावीरा ग्वालियर , Best Deput सृजन बैतूल , बेस्ट सचिव आरजू गोठी, वृक्षारोपण में विदिशा केन्द्र , चिकित्सा संवर्धन में सृजन बैतूल एवं सेवा में भोपाल केन्द्र को पुरस्कृत किया गया ।सभी केन्द्रों ने अपने कार्यो का ब्योरा भी प्रस्तुत किया ।वीर सोहन लाल जी, वीर पारस मलजी, वीर डॉ.पीतलिया जी सभी ने केन्द्रों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर आगे के लिए मार्गदर्शन दिया कैप्टन सुमीत सिंह जी ने महावीर इंटरनेशनल द्वारा किए जारहे कार्यों की सराहना की आपने भावुक होकर कहा कि फौजी को रिटायरमेंट के बाद कोई नहीं पूछता लेकिन महावीर इंटरनेशनल की वीराओं ने रक्षाबंधन पर राखी बाँधकर हमें सम्मान दिया ।

गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने सहित 30 मांगों को लेकर निकली प्रार्थना यात्रा

● **गो सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए देशभर में चल रहा जनजागरण अभियान**

बैतूल। गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत सोमवार को गोमाता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान की मांग को लेकर शहर में विशाल प्रार्थना यात्रा निकाली गई। सैकड़ों गौभक्त हाथों में झंडे, तख्तियां और बैनर लेकर शांतिपूर्वक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां अपर कलेक्टर वंदना जाट को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एक लाख हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपा गया। अभियान के मीडिया प्रभारी राजेश मदान ने बताया कि यात्रा से पहले शहीद दीपक यादव चौक सदर में गोमाता और नंदी का पूजन कर श्रीराम जयराम जय जयराम मंत्र का सामूहिक जाप किया गया। सुबह 11 बजे शंखनाद के साथ यात्रा शुरू हुई। भगवान श्रीकृष्ण-बलराम की झांकी, गोमाता-बछड़े का स्वरूप तथा बैलगाड़ी पर रखा हस्ताक्षर पत्र यात्रा का प्रमुख आकर्षण रहा। भजन-कीर्तन और जयघोष के बीच जिलेभर से आए श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। अभियान के जिला प्रभारी गिरीश खंडेलवाल ने बताया कि देशभर में 15 करोड़ से अधिक नागरिकों के हस्ताक्षर एकत्र कर ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। ज्ञापन में गोहत्या निषेध के लिए केंद्रीय कानून बनाने, गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने, केंद्रीय गो मंत्रालय की स्थापना, गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा केंद्रीय गो-चारा नीति लागू करने सहित 30 से अधिक मांगें रखी गई हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान संत सर्वेंद्र दासजी, प्रमोद शुक्ला महाराज, धर्मप्रकाश महाराज, प्रमोदानंद महाराज, रामआशीष दास, मुकेश दास, गोविंददास महाराज, रूपलाल रघुवंशी

महाराज, दिलीप अग्रवाल महाराज, अभियान प्रभारी गिरीश खंडेलवाल, समाजसेवी राजीव खंडेलवाल, बलराम जसूजा, बलवंत मदान, राजेश मदान, विजय हारोड़े, रविशंकर पारखे, संजय शुक्ला, दुर्गेश दुबे, प्रकाश गोठी, राजेश मेहता, श्रीमती ममता खंडेलवाल, श्रीमती राखी खंडेलवाल, सरपंच प्रियंका ठाकुर, दीपक कपूर, उत्पल शुक्ला, उत्तम गायकवाड़,

नारायण जसूजा, मनोज वर्मा, संजय पाल, डोरेलाल मालवीय, प्रभुदयाल सोनारे, आशीष साहू, सुभाष महस्की, कैलाश सोनी, मिथुन चिरपाटला, अखिलेश सिंह, दीपक अटलानी, दीपक पाल, दीपक मालवी, युवराज मालवीय, योगेश रोचलानी, अनिल यादव, इंदल यादव सहित विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

न्यायालयीन प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें : कलेक्टर डॉ. सोनवणे

बैतूल। मध्यप्रदेश शासन की कैरियर काउंसलिंग योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से इच्छुक आवेदकों को कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने के लिए काउंसलर्स की टीम गठित की जाना है, जो प्रतियोगी परीक्षा एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी एवं मार्गदर्शन देंगे। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि काउंसलर्स/ विषय-विशेषज्ञ को प्रत्येक काउंसलिंग मार्गदर्शन दिवस के 1 हजार मानदेय दिया जाएगा। काउंसलर/ विषय-विशेषज्ञों के पैनल के लिए कैरियर मार्गदर्शन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले आवेदकों के आवेदन जिला रोजगार कार्यालय बैतूल में 15 जुलाई तक चाहे गये थे, किन्तु पर्याप्त आवेदन प्राप्त न होने के कारण समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तिथि 10 अगस्त तक आगे बढ़ाई गई है।

● **काउंसलर्स पैनल में आवेदन करने के लिए योग्यता** – उन्होंने बताया कि मनोवैज्ञानिक पद के लिए मनोवैज्ञानिक विषय से स्नातक/स्नातकोत्तर अनिवार्य है। विषय विशेषज्ञ पद के लिए कला संकाय से पीएचडी, एमफिल तथा तकनीकी विषय से आईटीआई डिप्लोमा/डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं मेडिकल संकाय से एमबीबीएस, बीएचएमएस, एमडीपीजीडीएमएच योग्यता अनिवार्य है। विज्ञान एवं वाणिज्य विषय से स्नातक/स्नातकोत्तर अनिवार्य है।इसके अलावा एडमिशन्स, स्कालरशिप प्रतियोगी परीक्षा एवं रोजगार प्रशिक्षण के क्षेत्र में मार्गदर्शन एवं परामर्श देने का अनुभव एवं योग्यता रखना अनिवार्य है।

मौन साधना शिविर के साथ हुई विचार गोष्ठी

शिविर में 135 साधक हुए शामिल

बैतूल/चिचोली। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में देशभर में साधनाओं का दौर चल रहा है ।गायत्री जयंती से गुरु पूर्णिमा तक अनेक साधक अनुष्ठान कर रहे हैं। इसी कड़ी में चिचोली जिला बैतूल में जिला स्तरीय एकदिवसीय मौन साधना का आयोजन किया गया। जिसमें मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप किया। । उपजोन सिवनी के सौसर से पधारे उपजोन साधना आंदोलन प्रभारी नरेंद्र हिंगवे, शिवाजी ठाकरे, चित्रसेन रबडे व राजकुमार पालीवाल ने विधि विधान से पूजन कराकर मौन साधना का शुभारंभ कराया तथा परिजनों को मौन साधना के महत्व से अवगत कराया। जिला स्तरीय मौन साधना में बैतूल जिले की समस्त तहसीलों से तहसील प्रभारी के साथ अन्य परिजन भी उपस्थित हुए । जिला समन्वय समिति के मार्गदर्शन में समस्त तहसीलों में इसी प्रकार साधनाएं करवाने का आवाहन किया गया। जिला समन्वयक रवि शंकर पारखे ने सभी तहसील समन्वयको और परिजनों को साल भर चलने वाले अभियानों से परिचित कराया एवं कार्यक्रमों की रिपोर्ट प्रति माह समय पर प्रेषित करने के निर्देश दिए व गुरु पूर्णिमा पर्व पर विद्यारंभ संस्कार स्कूलों में आयोजित करने की बात कही।

प्रत्येक तहसील में 24 गांवों में गायत्री परिवार की गतिविधियों के संचालन की योजना बनाने का आह्वान किया। जिला साधना प्रभारी ने बताया कि आज 135 से अधिक साधकों ने शिविर में भाग लिया। बाल संस्कारशाला प्रभारी अजय पवार ने प्रत्येक तहसील में 10-10 बाल संस्कार शालाएं खुलवाने के लिए प्रेरित किया ताकि जिले के लक्ष्य को पूरा किया जा सके युवा प्रकोष्ठ के जिला समन्वयक अनूप वर्मा ने सुपर 100 कार्यक्रम के लिए प्रत्येक विकासखंड एवं तहसील से युवाओं को खोज कर निकालना एवं उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु मार्गदर्शन दिया वरिष्ठ परिजन रोशन लाल पटैया ने अपने पूर्व अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन दिया। जिला सह समन्वयक राजकुमार पालीवाल ने नियमित रूप से साधना करने का सुझाव दिया गणपति गायकवाड ने निकट भविष्य में कन्या कौशल शिविर आयोजित करने हेतु सुझाव दिए। चिचोली तहसील प्रभारी श्रीमती रजनी सोनी ने सभी का आभार व्यक्त किया। मौन साधना शिविर में स्थानीय परिजनों का सहयोग सराहनीय रहा।

■ शासकीय आदर्श महाविद्यालय, विदिशा की छह दिवसीय कार्यशाला का समापन

लक्ष्य स्पष्ट हो, तैयारी निरंतर हो तो प्रशासनिक सेवा में सफलता निश्चित

विदिशा (निप्र)। शासकीय आदर्श महाविद्यालय, विदिशा में आयोजित 'प्रशासनिक अधिकारी कैसे बनें' विषयक छह दिवसीय कार्यशाला का शनिवार को प्रेरणादायी एवं ज्ञानवर्धक वातावरण में समापन हुआ। समापन सत्र में प्रशासनिक सेवा, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को सफलता के व्यावहारिक सूत्र बताते हुए उनके प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दिए। वक्ताओं ने कहा कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, तैयारी निरंतर और अनुशासित हो तो प्रशासनिक सेवाओं में सफलता अवश्य प्राप्त की जा सकती है।

कार्यक्रम के विशेष अतिथि शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, विदिशा के प्राचार्य डॉ. बी.डी. अहिरवार ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा, विभिन्न सेवाओं के कैडर, चयन प्रक्रिया तथा प्रशासनिक सेवाओं में उपलब्ध अवसरों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नियमित अध्ययन, समय का प्रभावी प्रबंधन, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास ही प्रशासनिक अधिकारी बनने की मजबूत नींव हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को वर्तमान घटनाक्रम, सामान्य अध्ययन और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान देने की सलाह भी दी। मुख्य अतिथि अजय गोयल, सहायक संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गणित, रीजनिंग और समय प्रबंधन की उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता केवल अधिक पढ़ने से नहीं, बल्कि सही रणनीति, नियमित अभ्यास और निरंतर आत्ममूल्यांकन से मिलती है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित कर योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन करने की प्रेरणा दी। विशिष्ट अतिथि भगवान सिंह बघेल, मुख्य शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, विदिशा ने बैंकिंग क्षेत्र में रोजगार और करियर की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते महत्व की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को बैंकिंग सेवाओं में उपलब्ध अवसरों, तकनीकी बदलावों तथा डिजिटल लेन-देन के सुरक्षित उपयोग के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में बैंकिंग क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार और विकास का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने विशेषज्ञों से डिजिटल बैंकिंग के लाभ एवं चुनौतियों, अध्ययन के दौरान मन को एकाग्र रखने के उपाय, साक्षात्कार की प्रभावी तैयारी, लक्ष्य निर्धारण तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की रणनीति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अनेक प्रश्न पूछे। विशेषज्ञों ने व्यावहारिक उदाहरणों और अपने अनुभवों के आधार पर विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया, जिससे उन्हें अपने करियर की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। समापन समारोह में चीरखेड़ा के सरपंच अरुण शर्मा, जाफरखेड़ी के सरपंच हुकुम सिंह लोधी तथा खमतला के सरपंच प्रदीप मिश्रा भी उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर निरंतर प्रयास करने का संदेश दिया।

एक पेड़ मां के नाम' अभियान में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की हरित पहल, एनसीसी कैडेट्स ने लगाए 150 पौधे

विदिशा (निप्र)। पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में शनिवार को 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की एनसीसी यूनिट, एनएसएस स्वयंसेवकों तथा विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए महाविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के 150 पौधों का रोपण किया। इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने पौधों के संरक्षण और नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम का आयोजन एनसीसी अधिकारी डॉ. राजकमल प्रजापति के संयोजन में किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. वनिता बाजपेई मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प ले, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को प्रकृति और मातृत्व के प्रति सम्मान व्यक्त करने वाली प्रेरणादायी पहल बताते हुए विद्यार्थियों से इसे जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. सुनील कुमार जैन, डॉ. डी.पी.सी. नरवरिया, डॉ. रश्मि यादव, डॉ. राजकुमार भीमटे, डॉ. प्रमोद सेन, डॉ. बृजेश साहू, श्रीमती श्वेता सोलंकी, डॉ. निमिषा वर्मा, सुश्री आकांक्षा अहिरवार, श्री संदीप त्रिपाठी एवं श्री अंकित दुबे सहित अन्य प्राध्यापक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों तथा महाविद्यालय के लगभग 100 विद्यार्थियों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए परिसर में छायादार, फलदार एवं पर्यावरण के अनुकूल विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। विद्यार्थियों ने पौधों की नियमित देखभाल, संरक्षण और संवर्धन का सामूहिक संकल्प लेते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। महाविद्यालय परिवार ने इस अभियान को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रेरक पहल बताते हुए भविष्य में भी ऐसे जन-जागरूकता एवं प्रकृति संरक्षण से जुड़े रचनात्मक कार्यक्रमों का निरंतर आयोजन करने का संकल्प व्यक्त किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम ने परिसर में हरियाली बढ़ाने के साथ-साथ विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी सुदृढ़ किया।

■ सीआईएस एवं ई-कोर्ट सेवाओं की दी गई व्यवहारिक जानकारी

डिजिटल न्याय व्यवस्था और साइबर सुरक्षा का मिला प्रशिक्षण

विदिशा (निप्र)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदिशा द्वारा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री शेख सलीम के मार्गदर्शन में शनिवार को एडीआर भवन के सभागार में पैरालीगल वालेंटियर्स के दक्षता संवर्धन के उद्देश्य से सीआईएस (कोर्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम) एवं साइबर सुरक्षा विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य पैरालीगल वालेंटियर्स को डिजिटल न्याय व्यवस्था, ई-कोर्ट सेवाओं तथा साइबर अपराधों से बचाव संबंधी व्यावहारिक जानकारी देकर उन्हें आमजन तक इन सेवाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए सक्षम बनाना था। श्री शेख सलीम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था तेजी से डिजिटल स्वरूप ग्रहण कर रही है। ऐसे समय में पैरालीगल वालेंटियर्स की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि यदि वालेंटियर्स डिजिटल न्यायिक सेवाओं की पूरी जानकारी प्राप्त कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं तो न्याय को अधिक सुलभ, सरल और पारदर्शी बनाया जा सकता है। उन्होंने सभी वालेंटियर्स से तकनीकी रूप से दक्ष बनने और आम नागरिकों को न्यायिक सेवाओं का लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री नितेन्द्र सिंह तोमर ने डिजिटल जस्टिस में पैरालीगल वालेंटियर्स की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ई-फाइलिंग, ई-पे, ई-समंस, ई-कोर्ट सेवाएं, केस स्टेटस, कॉज लिस्ट तथा अन्य ऑनलाइन न्यायिक सुविधाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाना वालेंटियर्स का महत्वपूर्ण दायित्व है। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और सुविधाजनक बन रही है, जिसका लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना आवश्यक है। प्रशिक्षण सत्र के दौरान जिला न्यायालय विदिशा के सिस्टम ऑफिसर श्री राजीव चतुर्वेदी एवं सिस्टम असिस्टेंट श्री ठाकुर दयालसिंह ने कोर्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (सीआईएस) की कार्यप्रणाली, उद्देश्यों एवं उपयोगिता पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने ई-कोर्ट मोबाइल एप एवं सिटीजन सर्विसेज पोर्टल का लाइव प्रदर्शन करते हुए प्रतिभागियों को केस स्टेटस देखने, कॉज लिस्ट प्राप्त करने तथा अन्य ऑनलाइन न्यायिक सेवाओं का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। इस प्रदर्शन से पैरालीगल वालेंटियर्स को डिजिटल माध्यम से न्यायिक जानकारी प्राप्त करने और नागरिकों को इन सेवाओं से जोड़ने की प्रक्रिया समझने का अवसर मिला।

तीन प्रकरणों में जिला बदर के आदेश जारी

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अंशुल गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक के पालन प्रतिवेदन पर तीन प्रकरणों में जिला बदर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभिन्न अपराधों में लिप्त अनावेदक प्रकाश अहिरवार, मंजीत दांगी और सूरज खटीक सहित प्रत्येक की जिला बदर कार्यवाही में समयावधि क्रमशः 6-6 माह अंकित है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गुप्ता के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि विभिन्न अपराधों में लिप्त आरोपी प्रकाश अहिरवार पिता कल्याण सिंह अहिरवार उम्र 36 साल निवासी रंगियापुरा विदिशा थाना कोतवाली विदिशा तथा अनावेदक मंजीत दांगी पुत्र करन सिंह दांगी निवासी गली नम्बर दो बरईपुरा थाना कोतवाली विदिशा तथा अनावेदक सूरज खटीक पिता मोहन खटीक उम्र 36 साल निवासी ढलकपुरा थाना कोतवाली विदिशा सहित तीनो को क्रमशः छह-छह माह के जिला बदर की कार्यवाही की गई है। उक्त अवधि में विदिशा एवं सीमावर्ती जिले, रायसेन, भोपाल, गुना, अशोकनगर, सागर एवं राजगढ की राजस्व सीमाओं से निष्काषित किया गया है। अनावेदको के इन जिलो के न्यायालयों में यदि कोई राजस्व, आपराधिक मामले गतिशील हो तो उन मामलो में तारीख पेशी के दिन उन जिलों के न्यायालय में आ एवं जा सकेगा इसके लिए अनावेदक को संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित थाना प्रभारी को सूचना देना अनिवार्य होगा।

संक्षिप्त समाचार

एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत ग्राम उमरी किला खंडारा में किया पौधरोपण

बैतूल (निप्र)। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को ग्राम उमरी किला खंडारा में 50 आम एवं जामुन के पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाना तथा फलदार वृक्षों के माध्यम से प्रकृति और समाज को दीर्घकालिक लाभ पहुंचाना रहा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संभाग समन्वयक श्री कौशलेश तिवारी, जिला समन्वयक श्री संतोष सिंह राजपूत, नवांकुर संस्था अंश सेवा समिति, बैतूल से श्रीमती सावी मालवीय तथा ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के श्री भवानी शंकर, श्री नकुल भुसारे एवं श्री राजेंद्र रावत, श्रीमती संतोषी रावत सुखदेश भुसारे, राम चढोकार उपस्थित रहे। सभी उपस्थितजनों ने पौधारोपण के साथ पौधों के संरक्षण एवं नियमित देखभाल का संकल्प लिया तथा अधिक से अधिक लोगों से 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण में अपनी सहभागिता निभाने का आह्वान किया।

विशेष मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ

विदिशा (निप्र)। राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय कन्या अग्रणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय विदिशा में विद्यार्थियों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण के उद्देश्य से एक विशेष मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय विदिशा से मनोचिकित्सक डॉ अशोक राजपूत , नैदानिक मनोवैज्ञानिक श्री रवि सिंह सेंगर एवं मनोचिकित्सा नर्सिंग अधिकारी श्री गिरिराज सैनी ने छात्राओं को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को तनाव प्रबंधन, करियर के दबाव से निपटने और खुलकर अपनी बात रखने के तरीकों पर मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही छात्राओं को जिला चिकित्सालय में संचालित 'मन क्लीनिक और टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर से अवगत कराया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि 'मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना या मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत पहचानना है। यह कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ बी डी अहिरवार के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ तथा मानसिक स्वास्थ्य क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया ।इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के स्टाफ ने भाग लिया तथा छात्राओं को एक सुरक्षित और सहयोगी माहौल देने का भरोसा दिलाया। छात्राओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और अपनी मानसिक परेशानियों व शंकाओं को साझा किया। कार्यक्रम का संचालन एनटीएफ प्रभारी प्रो.नीतू दांगी द्वारा सफलतापूर्वक किया गया।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर शिविर लगाकर किया गया 571 बच्चों का टीकाकरण

सीहोर (निप्र)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिलेभर में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं एवं अनेक स्थानों पर प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत शिविर लगाकर टीकाकरण के साथ ही बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। इसी क्रम में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के तहत जिले में 24 जुलाई को आयोजित शिविरों में शून्य से एक वर्ष की आयु के 364 बच्चों तथा एक वर्ष से अधिक आयु के 207 बच्चों का टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही 86 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट को जांचने जिले में चलाया जा रहा विशेष निगरानी अभियान

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ.सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन दल द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की जांच के लिए विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत दल द्वारा बैतूल में कोसमी औद्योगिक क्षेत्र में जांच कर हेल्दी बाईट डेयरी एवं प्रोडक्ट, ब्रज डेयरी से घी का 01 पनीर 01 एवं दूध के 02 नमूने लिए गए। इसके अलावा दल द्वारा मुलताई में जांच अभियान चलाकर मां ताप्ती डेयरी, सरोज मिल्क प्रोडक्ट, धनश्री एजेंसी एवं सरोज डेयरी से दूध के 05 नमूने व दही का 01 नमूना संग्रहित किया गया। आमला तहसील से दल द्वारा रेणुका किराना व गुड़िया किराना से घी के 2 व दूध के 02 नमूने संग्रहित किए गए। लिए गए नमूनों को राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।

नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को डीबीटी एवं कौशल विकास योजनाओं का दिया गया प्रशिक्षण

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले में नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके दायित्वों के प्रभावी निर्वहन तथा विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में आयोजित इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों के अधिकारी सहभागिता कर रहे हैं तथा कार्यकर्ताओं को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं विभागीय प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके कार्यों में दक्ष बनाना, विभिन्न विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों एवं उनके समाधान के संबंध में भी मार्गदर्शन दिया। प्रशिक्षण सत्र में लीड बैंक अधिकारी श्री बी.एस. बघेल ने कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शासन की विभिन्न हितग्राही योजनाओं की राशि अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। उन्होंने बैंक खाते, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी, डीबीटी भुगतान की प्रक्रिया तथा हितग्राहियों को मिलने वाले लाभों की जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं से पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। इसी क्रम में आईटीआई की प्राचार्य श्रीमती कविता रघुवंशी ने व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास पर आधारित सत्र को संबोधित किया।

उन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में संचालित विभिन्न ट्रेडों, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों, स्वरोजगार एवं कौशल विकास के अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के युवाओं एवं अभिभावकों को आईटीआई में उपलब्ध रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के प्रति जागरूक कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने, हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने तथा विभागीय समन्वय के साथ जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर नवनियुक्त कार्यकर्ताओं ने भी प्रशिक्षण में सक्रिय सहभागिता करते हुए विभिन्न विषयों पर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया।

आयुष विभाग ने 455 गर्भवतियों का कराया गर्भ संस्कार

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशु के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आयुष विभाग द्वारा जिले में गर्भ संस्कार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिले के सभी 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित कुल 14 केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रम में 455 गर्भवती महिलाओं को गर्भ संस्कार कराया गया। जिला आयुष अधिकारी डॉ. योगेश चौकीकर ने बताया कि गठित आयुष चिकित्सकों की टीम द्वारा प्रत्येक माह की 9 और 25 तारीख को होने वाले इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को गर्भ संस्कार के महत्व, मातृ स्वास्थ्य तथा गर्भस्थ शिशु के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास पर इसके सकारात्मक प्रभावों की जानकारी दी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार गर्भावस्था के दौरान मां के विचार, भावनाएं, आहार और दिनचर्या का सीधा असर गर्भस्थ शिशु के विकास पर पड़ता है।

मिलावट के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान जारी

● दूध-दही सहित विभिन्न दुग्ध उत्पादों के लिए नमूनें

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जिले में मिलावट के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य आमजन को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न दूध विक्रेताओं, डेयरियों एवं दुग्ध शीत केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती किरण एम. श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान के तहत गंजबासौदा स्थित सिरोंज रोड के दुग्ध शीत केंद्र से मिश्रित दूध का नमूना जांच के लिए लिया गया। वहीं आज 25 जुलाई को विदिशा शहर के तिलक चौक स्थित श्री धी डेयरी एंड प्रोडक्ट्स का निरीक्षण कर टोंड मिल्क, स्कीम मिल्क तथा दही के नमूने संग्रहित किए गए। संग्रहित सभी नमूनों को गुणवत्ता एवं मानकों की जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है। प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं को स्वच्छता, गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा मिलावट करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं मिलावटी अथवा संदिग्ध खाद्य पदार्थों का विक्रय होने की जानकारी मिले तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें, ताकि समय पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जिले में मिलावट के विरुद्ध यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

बैठक लेकर आगामी कांवड़ यात्रा के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के दिए निर्देश

प्रभारी मंत्री ने की कुबेरेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

सीहोर (निप्र)। कुबेरेश्वर धाम में आयोजित गुरू पूर्णिमा महोत्सव और आगामी कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत पिछड़ा वर्ग मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने रेस्ट हाउस तथा कुबेरेश्वर धाम पर बैठक आयोजित कर आयोजन की सभी व्यवस्थाओं के संबंध में बिंदुवार चर्चा की तथा संबंधित अधिकारियों एवं आयोजन समिति को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोजन में बाड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए सभी तैयारियां चाक चौबंद रखी जाएं, ताकि आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था, असुविधा अथवा सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न न हो। उनहोंने कहा कि समिति प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य सुनिश्चित करे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। कलेक्टर श्री बालगुरू के., एसपी श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना ने प्रभारी मंत्री को गुरू पूर्णिमा महोत्सव के लिए की गई व्यवस्थाओं तथा आगामी कांवड़ यात्रा के सुचारू आयोजन की कार्ययोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराया। बैठक में यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था की जानकारी लेते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में जाम की समस्या न बने। पार्किंग स्थलों का स्पष्ट चिन्हांकन, अलग-अलग पार्किंग जोन निर्धारण तथा वाहनों की सुव्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित की जाए। हाईवे एवं मुख्य मार्गों पर प्रभावी डायवर्जन प्लान लागू रहे तथा पर्याप्त संकेतक, फ्लेक्स व सूचना बोर्ड लगाए जाएं।

उन्होंने अनाउंसमेंट सिस्टम सतत संचालित रखने तथा फायर ब्रिगेड, अग्निशमन उपकरण व आपातकालीन व्यवस्थाएं उपलब्ध रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रवेश-निकास द्वार, पार्किंग, कंट्रोल रूम एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं के संबंध में भी निर्देश दिए। इसके साथ ही सीवन नदी से कुबेरेश्वर तक आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए।

पंडित प्रदीप मिश्रा से की चर्चा

प्रभारी मंत्री श्रीमती गौर ने कुबेरेश्वर धाम पर पंडित प्रदीप मिश्रा एवं आयोजन समिति के साथ बैठक कर कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की । उन्होंने आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुचारु व्यवस्थाओं के संबंध में समिति से विस्तृत जानकारी प्राप्त की । उन्होंने कहा कि प्रशासन एवं आयोजन समिति आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक व्यवस्था को समय पर पूर्ण करें, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े ।

मध्य प्रदेश में घट रहे हैं मिलावट के आंकड़े

लेकिन कम होती जांच और लैब की खस्ताहाली ने बढ़ाई चिंता

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में असुरक्षित और मिलावटी खाने के मामले कम जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता बढ़ गई है। इसके पीछे असल वजह यह है कि विभाग द्वारा फूड सैंपलिंग का काम ही कम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन सालों में जहां एक तरफ मिलावट के नियमों का उल्लंघन करने वाले मामले घटे हैं, वहीं दूसरी तरफ सैंपलिंग में भी 11.1 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई है। सैंपलिंग और पकड़े जाने वाले मामलों के बीच का यह अंतर अब इस बात पर सवाल खड़े कर रहा है कि क्या खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक सख्ती कम हो गई है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में साल 2023-24 के दौरान कुल 13,998 खाद्य नमूनों की जांच की गई थी, जिनमें से 2,022 सैंपल मानक के अनुरूप नहीं पाए गए थे। इसके बाद साल 2024-25 में 13,920 सैंपल टेस्ट हुए और 1,635 सैंपल मिलावटी या सबस्टैंडर्ड निकले। वहीं, साल 2025-26 के शुरुआती और अनंतिम आंकड़ों में यह गिरावट और ज्यादा साफ दिखाई देती है, जिसमें 12,448 नमूनों की जांच हुई और केवल 757 सैंपल ही फेल घोषित किए गए। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि 2025-26 के ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं और आगे की जांच व अदालती कार्यवाही के बाद इनमें बदलाव हो सकता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी और लैब में नहीं था फूड एनालिस्ट

आम उपभोक्ता के लिए ये आंकड़े सिर्फ कागजी नहीं हैं, बल्कि सीधे तौर पर उनकी सेहत से जुड़े हैं। जब बाजार में सैंपलिंग कम होती है, तो मिलावटी सामान बिना पकड़े सीधे लोगों की थाली तक पहुंच जाता है। राज्य में एमपीएफडीए की बुनियादी सुविधाओं की पोल भी खुलती नजर आ रही है। फरवरी के दौरान स्थिति यह थी कि नियमित टेस्टिंग पूरी तरह ठप पड़ गई थी क्योंकि एजेंसी के पास ऑन-रोल कोई फूड एनालिस्ट ही नहीं था और माइक्रोबायोलॉजी लैब भी बंद पड़ी थी। छिंदवाड़ा में हुई कफ सिरप की दर्दनाक घटना के बाद विभाग की मॉनिटरिंग और लाइसेंसिंग प्रणाली पर गहरे सवाल खड़े हुए थे। कोल्ड्रिफ सिरप के जहरीले बैच के सेवन से 20 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई थी, जिससे विभाग की कार्यशैली कटघरे में आ गई थी। भले ही विभाग की तरफ से समय-समय पर मामले दर्ज किए जाते रहे हों, जैसे कि सिविल मामलों की संख्या 2023-24 में 1,938 से बढ़कर 2024-25 में 2,597 हुई और फिर 2025-26 में घटकर 1,790 पर आ गई, लेकिन घटती जांच का यह दायरा आम जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है।

खत्म हुआ इंतजार, भोपाल के निशातपुरा रेलवे स्टेशन से अब चलेंगी ट्रेनें

आज सीएम करेंगे लोकार्पण

भोपाल (नप्र)। निशातपुरा रेलवे स्टेशन महीनों पहले बनकर तैयार हो गया था। लेकिन वहां से ट्रेनें नहीं चल रही थीं। इस स्टेशन से गाड़ियां तो गुजरती थीं लेकिन किसी भी ट्रेन का कोई स्टॉपेज नहीं था। न ही कोई ट्रेन खुलती थी। इसकी वजह से लोग इस भूतिया स्टेशन भी कहने लगे थे। लेकिन 28 जुलाई से यहां से ट्रेनें चलने लगेंगी। सीएम मोहन यादव इस स्टेशन का लोकार्पण करेंगे।

मंत्री विश्वास सारंग ने किया निरीक्षण- उद्घाटन से पहले प्रदेश के खेल एवं युवा विकास मंत्री विश्वास सारंग ने मौके पर पहुंचकर इसका निरीक्षण किया है। साथ ही कार्यक्रम की तैयारियों को देखा है। अधिकारियों को उन्होंने समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

भोपाल को मिलेगी नई पहचान- मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि निशातपुरा रेलवे स्टेशन का संचालन केवल एक नए रेलवे स्टेशन

का शुभारंभ नहीं, बल्कि तेजी से विकसित हो रहे भोपाल की नई पहचान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई महत्वपूर्ण अधोसंरचना है। यह भोपाल के लाखों नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक सौगात साबित होगी।

उन्होंने बताया कि 28 जुलाई को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव निशातपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद स्टेशन से यात्री रेल सेवाओं का नियमित संचालन प्रारंभ होगा। इंदौर की ओर जाने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन निशातपुरा रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। विशेष रूप से मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ-जबलपुर एक्सप्रेस का ठहराव अब निशातपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा।

भोपाल में हो गए अब चार रेलवे स्टेशन- भोपाल शहर का विस्तार अब तेजी से हो रहा है। शहर के विस्तार के साथ-साथ सुविधाओं की भी जरूरत है। भोपाल शहर में अब चार रेलवे स्टेशन हो जाएंगे। पहले से भोपाल, रानी कमलापति और संत हिरदाराम नगर स्टेशन हैं। इसमें नया निशातपुरा स्टेशन का नाम जुड़ गया है।

इन्हें होगा ज्यादा लाभ- मंत्री सारंग ने कहा कि निशातपुरा रेलवे स्टेशन विशेष रूप से करोंद, निशातपुरा, छोला, भानपुर, अयोध्या बायपास, द्वारका नगर एवं आसपास के क्षेत्रों के लाखों नागरिकों के लिए बड़ी सुविधा लेकर आया है। अब इन क्षेत्रों के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए शहर के भीड़भाड़ वाले मुख्य रेलवे स्टेशन तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय की बचत होगी, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और यात्रियों को अधिक सुविधाजनक रेल सेवाएं उपलब्ध होंगी।

श्रीरामानुज संस्कृत परिसर रीवा में नए शैक्षणिक सत्र से सभी पाठ्यक्रमों का संचालन सुनिश्चित किया जाए : उप मुख्यमंत्री

पद सृजन एवं समयबद्ध भर्ती के निर्देश

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के श्रीरामानुज संस्कृत परिसर, लक्ष्मण बाग, रीवा के सुदृढ़ीकरण एवं संस्थागत विकास संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए परिसर में आवश्यक शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन का प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने तथा समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र से परिसर में प्रस्तावित सभी पाठ्यक्रमों का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध एवं अकादमिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक मानव संसाधन समय पर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप सभी आवश्यक पदों के सृजन एवं शीघ्र भर्ती की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु, कुलसचिव एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ बैठक कर इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।

मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी को विश्वस्तरीय संरक्षण एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने सोमवार को मंत्रालय में मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के उन्नयन एवं विस्तार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को मास्टर प्लान के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी का विस्तार केवल पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन, अनुसंधान और जन-जागरूकता को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्रीमती समीता राजौरा वास सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी मध्यप्रदेश की विशिष्ट पहचान है और इसे राष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्ट वन्यजीव संरक्षण एवं इको-टूरिज्म केंद्र बनाया जाए। बैठक में वर्ष 2026-27 से 2045-46 तक की अवधि के लिए तैयार मास्टर प्लान की समीक्षा की गई।

मध्य प्रदेश में 18 महीनों में सड़क हादसों का डराने वाला आंकड़ा

90 हजार से ज्यादा दुर्घटनाओं में 25,800 से अधिक लोगों की मौत

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों की रफ्तार कितनी भयावह हो चुकी है, इस बात का खुलासा विधानसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों से हुआ है। राज्य सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में बीजेपी विधायक आशीष गोविंद शर्मा के एक लिखित सवाल के जवाब में बताया कि जनवरी 2025 से लेकर 7 जुलाई 2026 तक के 18 महीनों के दौरान पूरे प्रदेश में कुल 90,138 सड़क हादसे दर्ज किए गए। इन भीषण सड़क दुर्घटनाओं में कुल 25,869 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 95,843 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।

सदन में दी गई जानकारी के मुताबिक, इस अवधि के दौरान सबसे ज्यादा सड़क हादसे आर्थिक राजधानी इंदौर में दर्ज किए गए, जबकि मौतों के मामले में भिंड जिला सबसे आगे रहा। सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इंदौर में इस दौरान सबसे अधिक 5,404 सड़क हादसे हुए, जिसमें 4,443 लोग घायल हुए और 441 लोगों की मौत हुई।

मुख्यमंत्री ने सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को इस संगठन के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कर्तव्य निर्वहन के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सीआरपीएफ जवानों को नमन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की प्रभावशाली और दक्षतापूर्ण कर्तव्यनिष्ठा से ही देश में सांस्कृतिक विविधता में भी एकता अक्षुण्ण है।

सीएम ने श्री राजा मुथुपांडी को सिल्वर मैडल जीतने पर दी बधाई

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स - 2026 में पुरुषों की 65 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में सिल्वर मैडल जीतने पर श्री राजा मुथुपांडी को बधाई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्री मुथुपांडी का यह पदक देश के हर युवा को अपनी मेहनत से खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा एवं ऊर्जा देगा।

भाजपा राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करती है : हेमंत खण्डेलवाल

दतिया/भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल ने सोमवार को दतिया के मोटेल रिसोर्ट में रावत समाज के प्रबुद्धजनों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश और समाज को जोड़ने वाली पार्टी है। भाजपा ने सदैव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए सभी वर्गों और समाजों को समान सम्मान एवं अवसर प्रदान करने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा किसी एक वर्ग या समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति के विकास और सम्मान के लिए कार्य करती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक जनहितकारी योजनाएं लागू की हैं, जिनका लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचा है।

बिजली गिरने से 3 की मौत, 5 घायल

इटारसी में बरसात के लिए शिवलिंग को जल में डुबोया; अगले 4 दिन हैवी रेन का अलर्ट

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग मानसूनी सिस्टम एक्टिव होने से एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। रविवार को प्रदेश के पूर्वी हिस्से में तेज बारिश हुई, जबकि सोमवार को 6 जिलों में हैवी रेन यानी भारी बारिश का अलर्ट है।

मौसम विभाग भोपाल के मुताबिक, अगले 24 घंटे में उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अनुमान है। इस बीच शहडोल जिले में रविवार को तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 11 साल का बच्चा भी शामिल है। सभी घटनाएं खेतों और खुले स्थानों पर हुईं। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

शहडोल के जैतपुर थाना क्षेत्र में पहली घटना झींक बिजुरी चौकी के ग्राम झींक में हुई। यहां धान की रोपाई कर रहे लोगों पर आकाशीय बिजली गिरने से किशन (28) पत्नी राकेश गंभीर रूप से घायल हो गईं।

उन्हें झींक बिजुरी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलने पर जिला अस्पताल शहडोल रेफर किया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना में दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत स्थिर है।

प्रदेश में यह सिस्टम एक्टिव- मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि प्रदेश से एक मानसून ट्रफ गुजर रही है। वहीं, लो प्रेशर एरिया (निम्न दाब क्षेत्र) और डिप्रेशन भी एक्टिव है।

इटारसी में जल्द मेघ बरसाने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना

इटारसी में बारिश न होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इसी को देखते हुए प्राचीन तिलक सिंदूर मंदिर में रविवार को तिलक सिंदूर क्षेत्र में बम बाबा समिति ने भगवान भोलेनाथ का विशेष जलाभिषेक और अनूठा धार्मिक अनुष्ठान किया। अच्छी वर्षा, किसानों की समृद्धि और क्षेत्र में खुशहाली की कामना के साथ शिवलिंग को पूरी तरह जल में डुबो दिया गया। श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान भोलेनाथ को जल में विराजमान करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और अच्छी वर्षा होती है। रविवार सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का आना शुरू हो गया था।

असली 'सिस्टम' तो ऐसे ही धुरंधरों के हाथ में रहता है!

मोहन का मंत्रालय
आशीष चौधरी

प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, मुख्यमंत्री डा मोहन यादव की ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली भी पसंद है। उस पर निवृत्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन की सहमति ने श्री बर्णवाल के मुख्य सचिव बनने के रास्ते को और स्पष्ट कर दिया। नए मुख्य सचिव की कुशल कार्य-प्रणाली का क्या कहना! एकाग्रता से काम करना, हर महफिल में हंसमुख रहना और टारगेट को ऐसे भेदना जैसे अर्जुन की आंख। यही वजह है कि चाहे कमलनाथ सरकार आई हो या शिवराज की ताजपोशी हुई हो, सीएस बर्गवाल ने सीएम सचिवालय में तीन साल से अधिक का लंबा और शानदार वक्त गुजार लिया है। प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी चीता प्रोजेक्ट को ज़मीन पर उतारने का हुनर भी अशोक बर्णवाल के ही हिस्से आया, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ इनकी ट्यूनिंग इतनी पक्की थी कि वे खुद इन्हें मुख्यमंत्री के दरबार में लेकर हाजिर हुए और इनकी ताजपोशी पर मुहर लगवा लाए। साफ है, सरकारें आती-जाती रहेंगी, लेकिन असली 'सिस्टम' तो ऐसे ही धुरंधरों के हाथ में रहता है!

रजिस्ट्री जेब में है, पर संपत्तिकर का ताला नहीं खुल रहा!

राजधानी के एक पॉश इलाके में महज़ 600 स्क्वेयर फीट का एक छोटा सा प्लॉट इन दिनों सत्ता के गलियारों में सबसे बड़ी पंचायत बना हुआ है। कमाल देखिए कि इस मामूली से टुकड़े पर एक प्रभावशाली मंत्री जी की ऐसी 'कृपा-दृष्टि' पड़ी है कि बरसों से इसका संपत्तिकर तक जमा नहीं हो पा रहा है! मालिक के पास दशकों पुरानी लिंक पुश्तैनी रजिस्ट्रियां मौजूद हैं, लेकिन नगर निगम के दफ्तरों में फाइल ऐसे चक्कर काट रही है जैसे किसी सुपर-वीआईपी का वीजा लग रहा हो। वार्ड से लेकर जोन दफ्तर तक फाइल ने पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा लिए, पर मंजिल नदारद। कानून कहता है कि ज़मीन का अधिग्रहण हो और मुआवजा मिले। लेकिन यहाँ तो साहब, ज़मीन पर धार्मिक बैनर-पोस्टर सज चुके हैं, जिन पर नेताओं के साथ मंत्री जी की मुस्कुराती हुई तस्वीरें भी शोभा बढ़ा रही हैं। नगर निगम के बाबू दबी जुबान में कह रहे हैं कि जब मामला 'ऊपर' का हो, तो नीचे वालों की बोलती बंद हो जाती है। अब जनता यही पूछ रही है—क्या राजधानी में टैक्स भरने के लिए भी रजिस्ट्री से ज्यादा मंत्री जी की मर्जी जरूरी है? क्या यह बंगाल के ममता राज की झलक नहीं है?

विभाग बना लकी कूपन

राज्य शासन में इन दिनों एक नया ट्रेंड जोर पकड़ रहा है-यदि आपको किसी बड़े संभाग का कमिश्नर बनना है, तो पहले खाद्य आयुक्त की कुर्सी पर अपनी हाजिरी लगानी होगी! सरकार ने हाल ही में कर्मवीर शर्मा को खाद्य आयुक्त से उठाकर सीधे भोपाल संभाग का कमिश्नर बना दिया। उनकी खाली कुर्सी पर भास्कर लक्ष्यकार साहब आए, लेकिन वे भी खाद्य आयुक्त की कुर्सी पर ठीक से जमे भी नहीं थे कि सरकार ने उन्हें सीधे इंदौर संभाग की कमान सौंप दी। अब प्रशासनिक गलियारों में यही चर्चा है कि खाद्य आयुक्त का यह पद अब बड़े संभाग की गारंटी वाला लकी कूपन बन गया है। पेट भरने की जिम्मेदारी से सीधे शहर चलाने की गद्दी तक का सफर अब मात्र एक ट्रांसफर दूर है!

'सेटिंग' या विदाई का बेहतरीन रिटर्न गिफ्ट?

इन दिनों सचिवालय के गलियारों में एक बड़े ही रसूखदार आईएएस अधिकारी की चर्चा जोरों पर है। साहब जिस मलाईदार और बेहद अहम महकमे की कमान संभाले हुए हैं, उसकी सीधी लाइन सीधे सत्ता के दरबार से जुड़ती है। सूत्रों की मानें तो साहब की ऊर्जा और प्रशासनिक कुशाग्रता अब फाइल निपटाने के साथ सेवानिवृत्ति के बाद की 'दूसरी पारी' की बैटिंग पिच तैयार करने में लग रही है। रिटायरमेंट अभी कोसों दूर है, लेकिन साहब ने अभी से ऐसे-ऐसे मोहरे फिट करना शुरू कर दिए हैं कि उनका रिटर्न उपहार पक्का हैं सूत्र बताते हैं कि साहब, आगाकी में प्रदेश होने वाले एक बड़े आयोजन की जिम्मेदारी संभालने के इच्छुक हैं।

पैरामेडिकल विद्यार्थियों के हित में पंजीयन प्रक्रिया होगी और सरल : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि पैरामेडिकल विद्यार्थी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों के हितों की रक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा समयबद्ध शैक्षणिक प्रक्रिया सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पंजीयन एवं परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाकर विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानियों से राहत दी जाये, जिससे उनका शैक्षणिक सत्र और भविष्य प्रभावित न हो। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल की अध्यक्षता में मंत्रालय में मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद की 26वीं वार्षिक बैठक आयोजित हुई।